परिणाम बजट

2007-2008

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

परिणाम बजट

2007-2008

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सार	**i-iii**
अध्याय **I** – परिचय	**1-5**
अध्याय **II** – परिव्यय और परिणाम	**7-43**
अध्याय **III** – सुधार एवं नीतिगत पहल	**45-48**
अध्याय **IV** – पूर्व निष्पादन की समीक्षा	**49-72**
अध्याय **V** – वित्तीय समीक्षा	**73-75**

कार्यकारी सार

विदेश मंत्रालय का परिणाम बजट कतिपय परिव्ययों और उपलब्धियों एवं परिणामों की मात्रा के बीच संबंध स्थापित करने और चल रहे कार्यक्रमों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए भी एक तंत्र उपलब्ध कराता है ।

मंत्रालय की भूमिका हमारे राष्ट्रीय हितों और अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों का संवर्धन करने की है । मंत्रालय का बजट परंपरागत रूप से गैर-योजना प्रकार का है जिसका कुछ लघु भाग योजनागत भी है; तथापि क्षेत्रीय मसलों में विस्तारित होती हुई हमारी भूमिका को सशक्त बनाने के लिए पड़ोसी देशों में विशाल विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसे देखते हुए योजनागत घटक काफी मात्रा में बढ़ जाना अनिवार्य है । इसके साथ ही साथ हमने अन्य क्षेत्रों में भी नए बाजार विकसित किए हैं और इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि हम अपनी तकनीकी और आर्थिक सहायता में वृद्धि करें (अध्याय -I) ।

मंत्रालय के बजट को तीन व्यापक समूहों में रखा जा सकता है:

1. मोटे तौर पर एक-तिहाई स्थापना लागत से संबंधित है, अर्थात विदेश मंत्रालय के सचिवालय और विदेश स्थित मिशनों तथा केंद्रीय पासपोर्ट संगठन की समग्र स्थापना पर होने वाला व्यय;

2. मोटे तौर पर एक तिहाई बाध्यकारी व्यय से संबंधित है; अर्थात एस डी ई और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को किया जाने वाला अनिवार्य अंशदान; और

3. मोटे तौर पर एक तिहाई अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग संबंधित है और शेष मंत्रालय के पूंजीगत परिव्यय से संबंधित है ।

यह व्यावहारिक नहीं होगा कि मंत्रालय के स्थापना लागत पर नेमी व्यय की मात्रा और समग्र उद्देश्यों को बताया जाए जैसे वेतन, कार्यालय व्यय, एस डी ई, अंतराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान आदि, क्योंकि इन्हें मूल्यांकन के लिए लेखे में नहीं लिया गया है । परिणाम बजट का केंद्र बिंदु तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर व्यय तथा मंत्रालय के पूंजीगत व्यय पर है । कार्यकलापों के परिणामों के एक मात्रात्मक मूल्यांकन का प्रयास किया गया है जो कि कुल बजट के आधे से भी कम की मात्रा इंगित करता है और इसमें कोंसली कार्य के लिए कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम; अनुदान सहायता वाली संस्थाओं की गतिविधियां; तकनीकी सहायता के अधीन चलाई गई विकास परियोजनाएं; प्रशिक्षण कार्यक्रम और पूंजीगत परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति शामिल है । तदनुसार अगले वित्त वर्ष 2007-08 के लिए इन शीर्षों के अधीन परिवयय के सामने परिणाम दर्शाने के लिए पहली बार एक वृहत् प्रयास (अध्याय-II) किया गया है । इसके अलावा गत वर्ष 2005-06 में और चालू वित्त वर्ष 2006-07 की प्रथम तीन तिमाही में किए गए परिव्यय का निष्पादन भी (अध्याय IV) लिया गया है । तैयार

की जा रही परियोजनाओं के लिए परिणाम अभिनिर्धारित करने की इस प्रक्रिया से और उसके बाद पूर्वानुमानित परिणाम के सामने वास्तविक निष्पादन मापन से, वास्तविक निष्पादन और वित्तीय निष्पादन दोनों ही रूपों में मंत्रालय को यह आधार मिला है कि उद्देश्यों और भावी कार्यक्रमों की योजना को परिभाषित किया जाए ।

परिणाम बजट तैयार करना अतःसंबद्ध प्रक्रिया है । परिव्ययों को परिणामों में परिणत करना न केवल मात्रात्मक लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक होता है बल्कि परियोजनाओं की एक यथार्थ और अंतःसंबद्ध आयोजना करना, नियमों और समय सीमाओं में आबद्ध रहना और उन्हें समीक्षा एवं पारदर्शिता के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होता है । हालांकि वित्तीय प्रबंधन का यह एक नया साधन है, मंत्रालय ने कार्यक्रम क्रियान्वयन में डिजाइन, सुपुर्दगी, निगरानी और मूल्यांकन के लिए पहले से ही तंत्र विकसित कर लिया है ताकि इसके उपयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सके (अध्याय-III) ।

मंत्रालय ने परिणाम बजट का उपयोग प्रणालियों के सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया हैः

1. नीति निर्माता और लाभग्राहियों के बीच संचार संपर्क का संवर्धन - मंत्रालय और लाभग्राही सरकार/एजेंसी के बीच सहायता पैकेज के उल्लेख और उसकी परिभाषा के लिए नियमित संवाद । भूटान के मामले में हमारी सहायता" विकास योजना वार्ता" के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है;
2. नीतिगत दस्तावेजों की विषय-वस्तु में सुधार-परियोजना तैयार करने और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के परामर्श से परियोजना के ब्यौरे तैयार किए जाने के दौरान मेजबान देश में विद्यमान स्थितियों की विस्तृत जांच की गई है । म्यांमा में कालादन बहुविध परिवहन परियोजना के लिए म्यांमा के प्राधिकारियों के साथ तथा परियोजना को और परिष्कृत करने तथा मानदंड तैयार करने में भारतीय विशेषज्ञों के साथ भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है ;
3. क्रियान्वयन सक्षमता और वित्तीय सावधानी सुनिश्चित करना - वित्तीय मानकों को कड़ाई से लागू किया गया है, निरंतर अनुवीक्षण तथा उपाय लागू किए गए हैं जैसे परिनिर्धारित क्षति, निष्पादन गारंटी और परवर्ती शुल्क, उदाहरण के लिए टी सी आई एल द्वारा क्रियान्वित की जा रही पैन-अफ्रीका टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन नेटवर्क परियोजना में कार्यान्वयन की क्षमता में सुधार के लिए परिनिर्धारित क्षति, निष्पादन गारंटी और परवर्ती शुल्क संबंधी अनुच्छेद शामिल हैं ।
4. भागीदारी और निरंतरता की भावना जाग्रत करना-जहाँ संभव होता है, मंत्रालय स्थानीय प्राधिकारियों, समुदायों और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है और साथ ही साथ क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी और सक्षमताओं

के घटकों के साथ भी अधिकतर मामलों में परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था मेज़बान देश द्वारा की गइ है । कई बार निर्मित स्थान भी प्रदान किया गया । एक बार परियोजना पूर्ण होने पर, उस परियोजना को रख-रखाव के लिए स्थानीय निकायों को सौंपा जाता है । नेपाल और अफगानिस्तान में हमारी लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में न केवल स्थानीय प्राधिकारियों और समुदायों की प्रत्यक्ष भागीदारी है, अपितु स्थानीय लोगों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान भी है; और

5. समीक्षा और मूल्यांकन की संस्कृति का संवर्धन-सभी प्रमुख परियोजनाओं में मॉनिटरिंग, समीक्षा तथा मूल्यांकन का अन्तः-निर्मित तंत्र है । वर्ष 2007-08 के दौरान वृहद-परियोजनाओं के लिए बाह्य और स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था आरंभ करने का प्रस्ताव है । विदेशी छात्रों के प्रशिक्षण के लिए हमारा 'आइटेक' कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों और संस्थान द्वारा प्रदान किया गया अन्तः-निर्मित मूल्यांकन है, जबकि भूटान परियोजनाओं के निरंतर मूल्यांकन हेतु नियमित परियोजना मॉनीटरिंग समिति है ।

इस प्रक्रिया का अत्यधिक विशिष्ट प्रभाव समग्र लक्ष्यों तथा हितों पर विशुद्ध ध्यान करना है और उन्हें प्राप्त करने के तौर-तरीकों को प्रवर्तित करना है । प्रक्रिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि एक ऐसे युग में प्रवेश करना है जिसमें संपूर्ण उद्देश्यों और हितों पर ही विशुद्ध रूप से ध्यान केंद्रित हो और उन्हें प्राप्त करने के लिए तरीकों और साधनों का प्रवर्त्तन हो

" भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग अभिकरण " के नाम से एक अभिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है जो अन्य देशों को सहायता तथा तकनीकी सहायता देने के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन होगा । यह महसूस किया गया है कि व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा प्रबंधन किया गया ऐसा संगठन भविष्य के लिए योजना, कार्यान्वयन, समन्वय और मूल्यांकन में दक्षता को बढ़ाएगा ।

अध्याय I - परिचय

कार्य

विदेश मंत्रालय को भारत के विदेश संबंधों के सभी पहलुओं की देखभाल करने का कार्य सौंपा गया है । भारत सरकार की नियमावली, 1961(कार्य का आबंटन) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विदेश मंत्रालय को कार्य सौंपे गए हैं । इस भूमिका का निर्वहन करने में, मंत्रालय, नई दिल्ली स्थित मुख्यालयों में और 165 मिशनों, केंद्रों तथा संपूर्ण विश्व में विशेषज्ञता प्राप्त कार्यालयों और देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित प्रातिनिधिक कार्यालयों में, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों के जरिए राजनैतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में हमारे राष्ट्रीय हितों और हमारे नागरिकों के हितों के अनुसार कार्य करता है ।

लक्ष्य और उद्देश्य

भारत की विदेश नीति हमारे पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ बनाने, बड़ी शक्तियों और आर्थिक भागीदारों के साथ परस्पर लाभकारी संबंधों में संलग्नता, हमारे विस्तारित पड़ोस तथा अफ्रीका एवं लातिन अमरीका में स्थित देशों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने और सामाजिक-आर्थिक विकास तथा विश्व शांति में योगदान के निमित्त नई भागीदारियों को सृजित करने को प्राथमिकता देती है ।

सार्वभौमिकरण की दिशा में रुझान ऐसी नियम बद्ध प्रणालियों,जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ गहन एकीकरण का संवर्धन करते हुए विकासशील विश्व की आवश्यकताओं को पहचानती हों, की स्थापना को सुसाध्य बनाते हुए हमारे राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने हेतु, क्षेत्रीय ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की संवर्धित भागीदारी और आतंकवाद, निरस्त्रीकरण, पर्यावरण, मानवाधिकार, व्यापार एवं अन्य चुनौतियों सहित सार्वभौम मसलों पर समरुचि देशों के साथ समन्वय का आह्वान करते हैं।

हमारी विदेश नीति में आर्थिक और तकनीकी सहयोग की भूमिका का विस्तार हो रहा है, न केवल सहायता के लिए वित्तीय परिव्यय के अनुपात में, अपितु हमारे निवेश को चिह्नित करने वाली परियोजनाओं के भौगोलिक विस्तार और विविधता में भी । भारत हालांकि पारंपरिक रूप से दानकर्ता देश नहीं है, तथापि प्रशिक्षण सुविधाएं, सरकारी विकास सहायता उपलब्ध कराता है और निकटवर्ती देशों में और अफ्रीका एवं लातिन अमरीका में सामाजिक विकास और आधारभूत संरचना परियोजनाओं में भाग लेता है, न केवल उनके विकास प्रयासों की संपूरकता के लिए ही अपितु अपने अनुभवों में वृद्धि करने के लिए भी। भारत के ज्ञान क्षेत्र की सफलता विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्रों में, और निर्माण के क्षेत्र में हमारा कौशल भारत की अपनी शक्ति के उत्थान और इन उभरते हुए बाजारों में संभावना के अवसर उपलब्ध कराता है ।

व्यापक हितों और प्रतिबद्धताओं के साथ एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत ने मानवीय चुनौतियों का मुकाबला त्वरित गति से किया है और पीड़ितों को अनिवार्य आपदा राहत तथा पुनर्वास सहायता मुहैया कराने में अग्रणी रहा है ।

मृदु शक्ति के एक तत्व के रूप में सांस्कृतिक राजनय की भूमिका को सुदृढ बनाया गया है, न केवल हमारी प्राचीन सभ्यता को

प्रस्तुत करने हेतु, अपितु हमारे आधुनिक अनुभवों के रुचिकर घटनाक्रमों की झलक उपलब्ध कराने हेतु भी । मंत्रालय, प्रवासी भारतीयों के साथ गहन संपर्क बना कर रखता है और उन्हें विभिन्न सेवाएं मुहैया कराता है । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत तथा विदेश दोनों स्थानों पर सांस्कृतिक आदान-प्रदानों के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है ।

मंत्रालय, पासपोर्ट कार्यालयों और विदेश स्थित मिशनों के माध्यम से भारत और विदेश दोनों ही स्थानों पर भारतीय राष्ट्रिकों को सक्षम पासपोर्ट और कौंसली सुविधाएं उपलब्ध कराता है । मिशन, विदेशी राष्ट्रिकों को भारत यात्रा के लिए वीजा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं ।

मंत्रालय राजनयिक अधिकारियों के कौशल को निरंतर विकसित करने के प्रयास करता है । विदेश सेवा संस्थान विदेशी राजनयिकों को भी प्रशिक्षण मुहैया कराता है । विद्वान और विचारक समुदाय के साथ अधिकाधिक पारस्परिक क्रिया और सभ्य समाज के साथ संबंध बढ़ाने का लक्ष्य इस प्रक्रिया में साझेदारियों को व्यापक बनाना है और भारतीय विश्व कार्य परिषद मंत्रालय के प्रयास में महत्वपूर्ण रूप से हाथ बंटाता है । अचल संपत्तियों का अधिग्रहण और उनका प्रबंधन भी मंत्रालय की प्राथमिकता रहा है - ताकि सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों का एक पूल बनाया जा सके और किराया देयताओं को कम किया जा सके ।

संगठनात्मक स्थापना

विदेश मंत्रालय के प्रमुख विदेश मंत्री हैं जिनकी सहायता विदेश राज्य मंत्री करते हैं । आधिकारिक स्तर पर विदेश सचिव मंत्रालय के कार्यकरण की देखरेख करते हैं । सभी विदेशों के साथ हमारे द्विपक्षीय और राजनैतिक संबंधों की देखभाल करने के लिए मंत्रालय में प्रादेशिक प्रभाग हैं और नीति नियोजन, आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश संवर्धन, बहुपक्षी संगठन, क्षेत्रीय समूह, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, प्रेस एवं मीडिया संबंधी कार्य, कानूनी मामले, प्रोतोकोल, मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के कौंसली और प्रशासनिक पहलुओं की देखभाल करने के लिए विभिन्न कार्यात्मक प्रभागों को नामोद्दिष्ट किया गया है । इसके अलावा मंत्रालय का विदेश प्रशिक्षण संस्थान है और केंद्रीय पासपोर्ट संगठन तथा साथ ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय विश्व कार्य परिषद, चीनी अध्ययन संस्थान जैसी अनुदान-सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं ।

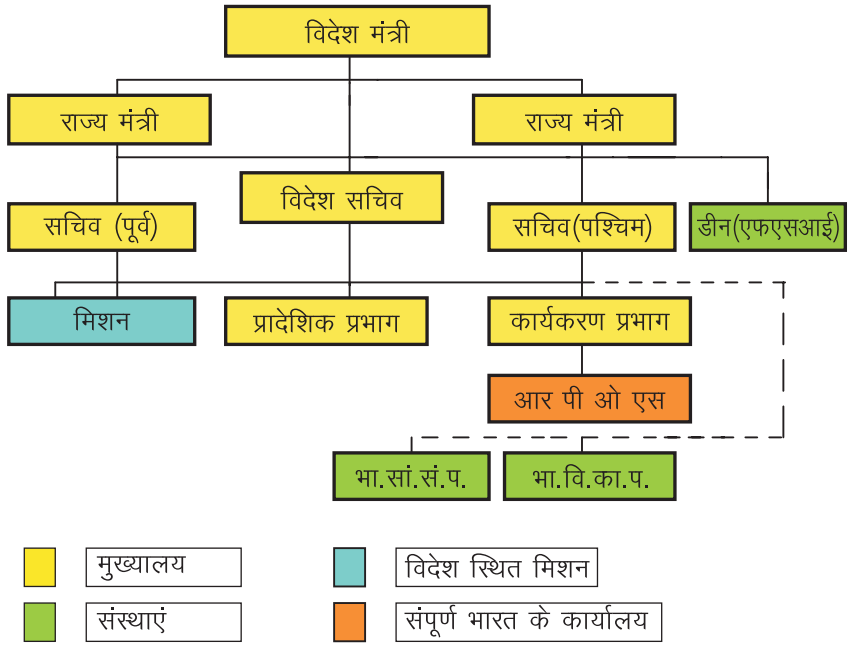

राजदूतावास, उच्चायोग, कोंसलावास तथा संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय संगठनों में स्थायी मिशन, मेजबान देश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रीय हित की संरक्षा तथा उसका संवर्धन करते हैं ।

नीतिगत रूपरेखा

भारतीय विदेश नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत पंचशील, उपयोगिता तथा राष्ट्रीय हितों के अनुपालन पर आधारित हैं । तीव्रता से और निरंतर परिवर्तनशील अवधि में विदेश नीति को नई चुनौतियों और नए अवसरों के लिए अनुकूलतम प्रतिक्रिया में सक्षम होना चाहिए । इसे आर्थिक विकास के जरिए राष्ट्र की क्षमताओं का निर्माण, सामाजिक ताने बाने और लोगों के कल्याण का सुदृढीकरण और भारत की संप्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता के संरक्षण के बृहद् प्रयास का एक अविभाज्य अंग होना होगा । शेष विश्व के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौम भू-राजनैतिक और आर्थिक वातावरण के यथार्थ, तथ्यपरक और समसामायिक मूल्यांकन पर आधारित प्रगतिशील संबंध ही भारत की विदेश नीति है ।

मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं

मंत्रालय के बजट को तीन व्यापक समूहों में रखा जा सकता है:

1. मोटे तौर पर एक-तिहाई स्थापना लागत से संबंधित है, अर्थात विदेश मंत्रालय के सचिवालय और विदेश स्थित मिशनों तथा केंद्रीय पासपोर्ट संगठन की समग्र स्थापना पर होने वाला व्यय;
2. मोटे तौर पर एक तिहाई बाध्यकारी व्यय से संबंधित है; अर्थात एस डी ई और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को किया जाने वाला अनिवार्य अंशदान; और
3. मोटे तौर एक तिहाई अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग संबंधित है और शेष मंत्रालय के पूंजीगत परिव्यय से संबंधित है ।

2006-07 (संशोधित अनुमान) और 2007-08 (बजट अनुमान प्रस्तावित) के लिए मंत्रालय के बजट में निधियों का क्षेत्रवार आबंटन नीचे लिखे अनुसार है । जैसा कि स्पष्ट है बड़े क्षेत्रों के भागों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है स्थापना प्रकृति के गैर-योजना मदों में किंचित वृद्धि हुई है, तकनीकी सहायता में 14% की वृद्धि हुई है, संवर्धित निर्माण गतिविधियों के कारण पूंजीगत परिव्यय में 56% की बढ़ोतरी हुई है; योजनागत आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में अनेक नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं ।

विदेश मंत्रालय के बजट का क्षेत्रवार आबंटन

क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रु. में)	
	सं.अ. 2006-07	ब.अ. 2007-08 (प्रस्तावित)
विदेश मंत्रालय सचिवालय	154.17	156.18
राजदूतावास एवं मिशन	951.41	990.01
पासपोर्ट और उत्प्रवासन	154.98	160.00
विशेष राजनयिक व्यय	923.01	850.01
अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	117.93	115.09
तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	1457.53	1663.95
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	62.50	70.00
विदेशी सरकारों को ऋ ण एवं अग्रिम	35.20	104.60
अन्य	78.32	73.77
पूंजीगत परिव्यय	160.00	250.00
कुल बजट	4095.05	4433.60

गैर-योजना आबंटन	3872.75	3933.60
योजना आबंटन	222.30	500.00
राजस्व	3899.84	3674.38
पूंजी	195.21	759.22
कुल बजट	4095.05	4433.60

- स्थापना प्रभार
- बाध्यकारी अंशदान/व्यय
- अनुदान सहायता/सहायता/पूंजीगत परिव्यय

क्षेत्रवार आबंटन
ब.अ. 2007-08 (प्रस्तावित)

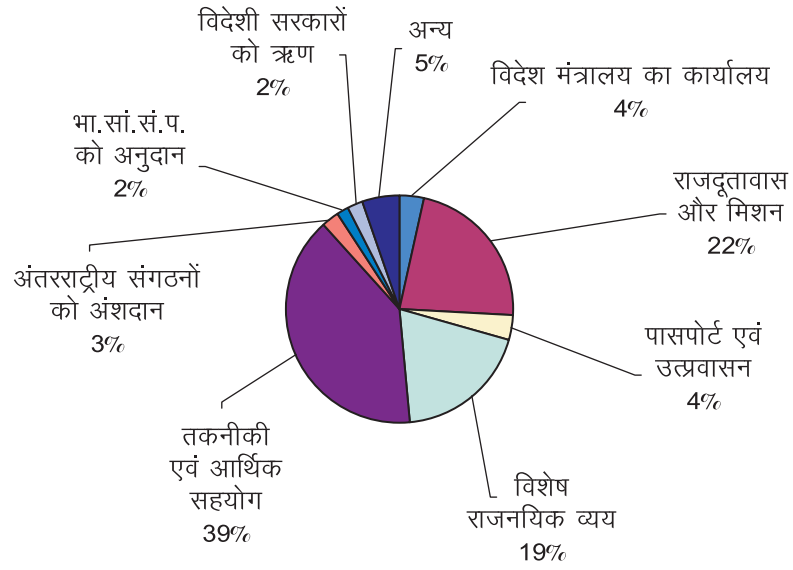

मंत्रालय के बजट का काफी बड़ा भाग पड़ोसी देशों और अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता के लिए चिह्नित किया जाता है । 2006-07 (सं.अ.) में हमारे सहायता एवं ऋण कार्यक्रमों के मुख्य लाभग्राही निम्नलिखित है । नीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, भिन्न-भिन्न देशों का हिस्सा कायक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को दर्शाता है ।

पड़ोसी देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता (सं. अ. 2006-2007)

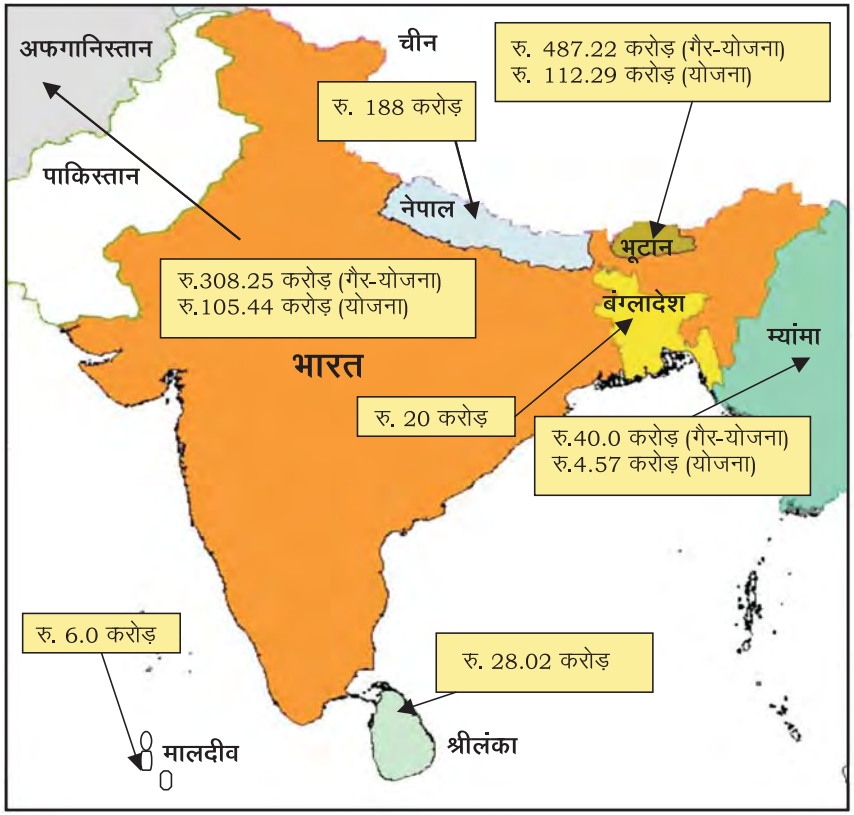

देश/क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रुपये)	
	सं.अ.2006-07	ब.अ.2007-08 (प्रस्तावित)
बंग्लादेश	20.00	15.00
भूटान	599.51	770.91
नेपाल	188.00	138.00
श्रीलंका	28.02	28.00
मालदीव	6.00	15.00
म्यांमा	44.57	80.41
अफगानिस्तान	413.69	473.55
अन्य विकासशील देश और स्कीम	82.69	109.68
आई टी ई सी और एस सी ए ए पी	71.25	68.00
अफ्रीकी देश	16.00	50.00
मध्य एशिया	17.00	20.00
कुल सहायता बजट	1486.76	1768.55

अध्याय II – परिव्यय और परिणाम

भारत सामाजिक और आर्थिक विकास के एक असाधारण दौर का अनुभव ले रहा है । सुधारवादी उपायों और नीतिगत पहलकदमियों, जिन्हें नवीकरण, उद्यम और विश्वास की नवचेतना के तहत घोषित किया गया, की शुरुआत करने से ही यह संभव हुआ है । सार्वभौमिक मसलों पर भारत के पदचिह्न विशाल आकार ले रहे हैं क्योंकि अंतरराट्रीय मामलों में भारत के योगदान के संबंध में आशाएं बढी हैं । राजनैतिक समझबूझ का संवर्धन, आर्थिक उत्थान का सृजन और नीतिगत उत्कर्ष को बनाए रखने के अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करने में और अवसरों से लाभ ग्रहण करने में मंत्रालय ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है ।

अन्य देशों के साथ और क्षेत्रीय समूहों के साथ संबंधों को संवर्धित करने के समग्र कार्य में मंत्रालय अन्य विकासशील देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, आपदा राहत और मृदु शक्ति प्रायोजना के अन्य प्रकार उपलब्ध करा रहा है । हमारी विदेश नीति का चूंकि यह अपेक्षाकृत बड़ा और सुस्पष्ट भाग है, विशेषरूप से घरेलू वृद्धि की प्रक्रिया इसे अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य बना देती है और इससे हमारे उभरते हुए क्षेत्रों को नई मंडियों में उछाल उपलब्ध होता है । ऐसे क्रियाकलापों के बढ़ते हुए बजटीय आबंटनों में यह परिलक्षित भी हुआ है ।

मंत्रालय के अधिकांश परिव्यय की एक विलक्षण विशेषता यह भी है कि इसमें उल्लिखित परियोजनाओं का क्रियान्वयन विदेशों में किया जाता है । प्रायः यह भी देखने में आया है कि प्राप्तकर्ता देश की राजनैतिक और सुरक्षा संबंधी गतिविधियां हमारी प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति में बाधा पहुंचाती हैं । इससे दूसरे पक्ष की संप्रभु सरकार के साथ परामर्श करना जरूरी हो जाता है ताकि परियोजना की संकल्पना, अभिकल्प, क्रियान्वयन, प्रबोधन, प्रबंधन, वित्तपोषण/सहायता की शर्तों इत्यादि पर परस्पर स्वीकार्य सहमति हो सके । तथापि परियोजना की शर्तों पर सहमति के लिए और पक्षकारों के बीच सहमति प्राप्त करने के लिए हर प्रयास किया जाता है, क्योंकि विदेशी वातावरण, जहाँ भारतीय पक्ष का प्रभावी नियंत्रण सीमित होता है, में कार्य संचालन की प्रकृति भिन्न होती है । इसीलिए समय और लागत में वृद्धि होने की संभावना रहती है । परिव्यय को परिणामों में परिणत करते समय इस दृष्टिकोण को ध्यान रखा जाना आवश्यक है ।

मंत्रालय की वृहत् परियोजनाएं भूटान और अफगानिस्तान में अवस्थित हैं और उनका वित्त पोषण "योजनागत" आबंटनों से किया जाता है । इन परियोजनाओं को सख्त व्यवहार्यता प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उनकी एक विस्तृत क्रियान्वयन अनुसूची होती है, इनकी एक सक्रिय प्रबोधन प्रक्रिया होती है और परिव्यय तथा परिणाम को भी स्पष्टतः तैयार करना होता है । भूटान में आधारभूत संरचना मुहैया कराने के अलावा इनसे हमें अतिरिक्त विद्युत एवं अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं । इन परियोजनाओं ने राजस्व वृद्धि की भूटान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता प्रदान की है और इससे भारत की वित्तीय सहायता पर भूटान की निर्भरता में कमी हुई है ।

ताला जलविद्युत परियोजना पूर्ण होने वाली है और पुनात्सांगछु -I जलविद्युत परियोजना के शीघ्र ही प्रारंभ होने की आशा है । इसी प्रकार पुल-ए-खुमरी से काबुल तक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण हो जाने से आशा है कि काबुल शहर को उजबेकिस्तान से भरोसेमंद विद्युत की आपूर्ति होगी । इस परियोजना से भारत के लिए सद्भावना का सृजन होगा और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे ।

मंत्रालय अफ्रीका और म्यांमा में भी बड़ी परियोजनाएं लगाना आरंभ कर रहा है । महत्वाकांक्षी पैन-अफ्रीका टेली-मेडिसिन और टेली-शिक्षा नेटवर्क सभी अफ्रीकी नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सभी अफ्रीकी देशों में चिकित्सालयों और विश्वविद्यालयों को भारत स्थित उनके समकक्षों से जोड़ेगा। म्यांमा में हमने कालादान बहुविध पारगमन और परिवहन परियोजना शुरू की है ताकि हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र को वैकल्पिक संपर्क उपलब्ध हो सके। यह परियोजना जिसमें सित्तवे में बंदरगाह, कालादान नदी पर जल मार्गों का विकास और भारतीय सीमा पर राजमार्ग का निमार्ण शामिल है, व्यापार प्रवाह और पूर्वोत्तर के एकीकरण को सुसाध्य बनाएगी ।

मंत्रालय, पड़ोसी देशों, क्षेत्रों में तथा साथ ही अफ्रीका और लातिन अमरीका में विभिन्न प्रकार की लघुतर परियोजनाओं में भी सलंग्न है । ये परियोजनाएं न केवल स्थानीय समुदाय की ही सहायता करती हैं अपितु उनके विकास कार्यों में हमारी संलग्नता को भी स्पष्ट करती हैं । सुधार उपायों और नीतिगत पहकदमियों का लक्ष्य है उन प्रणालियों की स्थापना जो निर्णय लेने में और परियोजनओं के क्रियान्वयन और प्रबोधन के लिए क्षमता प्रदान करती हैं । कार्य संचालन को ऐसा कारगर बनाने का प्रयास रहता है जिससे कथित समय सीमा और वित्तीय शर्तों के भीतर समग्र उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । हाल के समय में भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से सुधार उपायों एवं नीतिगत पहलों में निम्नलिखित शामिल है :

- भूटान में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित रहता है जिसे भूटान की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं में सीधे योगदान द्वारा संपूरित किया जाता है ।

- नेपाल में परियोजना के सभी पहलुओं में स्थानीय समुदाय के लोगों की महती संलग्नता रहती है ।

- अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के निर्माण में विशाल भागीदारी है ।

- बंगलादेश में स्थानीय समुदायों के विकास के लिए नई पहल शुरू की गई है ।

- म्यांमा में हम आधारभूत संरचनागत परियोजनाओं और सामाजिक विकास का कार्य कर रहे हैं । हमने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को वैकल्पिक संपर्क उपलब्ध कराने के लिए कालादान बहुविध पारगमन एवं परिवहन परियोजना भी शुरू की है ।

- दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों और साथ ही साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों का संवर्धन करने वाली विकासोन्मुख परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है । सुनामी पुनर्वास के लिए भी सहायता प्रदान की गई है ।

- अफ्रीका और लातिन अमरीका में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण और लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्यमों में हमारी क्षमताओं का उपयोग करने पर बल दिया गया है ताकि नए ढांचों के निर्माण को सुसाध्य बनाया जा सके ।

- कई क्षेत्रों में हमने राज्यों की क्षमता निर्माण और संस्थाओं की स्थापना जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है, करके, चुनाव कराकर, संसद की स्थापना करने में मदद करके सहायता प्रदान की है ।

2007-08 के लिए परिणामों और परिव्ययों की एक तालिका दी गई है :

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	विज्ञापन और प्रचार-प्रसार	क) फीचर फिल्म प्रारम्भ करना और खरीदना, वृत्त चित्र, फोटो/प्रदर्शनियों एएनआई एपिसोड/अंशदान आदि की डबिंग/स्क्रीनिंग ख) विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों के पुस्तकालयों के लिए विभिन्न प्रकाशनों का मुद्रण, पुस्तकों की खरीद और उन्हें विदेशी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्रस्तुत करना, विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों के लिए पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का मुद्रण और खरीद ग) 'भारत संदर्श' पत्रिका का प्रकाशन घ) भारत और विदेश स्थित प्रेस क्लबों, थिंक-टैंक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान के जरिए भारतीय विदेश नीति को परियोजित करना ड.) प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन, विदेश में विदेशी पत्रकारों की यात्राओं और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्राओं को देखना		25.00 (कुल) 8.00 8.35 (कालम 3 के (ख) से (ड.) के लिए)	• विदेश में प्रदर्शनी के लिए 40 फीचर फिल्मों और 20 वृत्त चित्रों को खरीदा जाएगा/डब किया जाएगा • भारत के बारे में बच्चों के किट की 10000 प्रतियां • भारत में और विदेशी संबंधों के बारे में हाल के घटनाक्रमों पर पुस्तकें (350 शीर्षकों की) विदेश में परिचालित की जाएंगी • 'भारत के विदेशी संबंध दस्तावेज 2007' की 500 प्रतियां • 'भारत संदर्श' की विदेशी भाषा में 65000 प्रतियां विदेश में परिचालित की जाएंगी	विदेश में भारत की छवि विशेषकर हमारे हाल के घटनाक्रमों और विदेश नीति संबंधी पहल के बारे में प्रभावी और सही छवि दर्शाना।	एक वर्ष (वार्षिक)	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
2.	पासपोर्ट और उत्प्रवासन	• पासपोर्ट कार्यालयों का नेटवर्किंग • हार्डवेयर का उन्नयन • पासपोर्ट फाइलों को स्कैन करना • यात्रा दस्तावेज का मुद्रण • मशीन से पठनीय प्रिंटरों का प्रावधान • विदेश स्थित चुनिंदा मिशनों में पासपोर्ट, वीजा और कांसुली सेवाओं का कंप्यूटरीकरण • स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट (एनआईएसजी) द्वारा पासपोर्ट कार्यालयों का कार्य अध्ययन		160.0	• केन्द्रीय डाटा-बेस को अद्यतन करना (पीआईएसओएन); • लगभग **50** लाख पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की फाइलों को स्कैन करना; • **51** लाख पासपोर्ट पुस्तिकाओं और **30** लाख वीजा स्टीकरों की खरीद • मशीन से पठनीय 33 प्रिंटरों की संस्थापना • वाशिंगटन, सैन्फ्रांसिस्को, शिकागो, ह्यूस्टन, दोहा, वानकोवर और मास्को में 7 मिशनों का कंप्यूटरीकरण • एनआईएसजी अध्ययन रिपोर्ट	• सीपीओ, पासपोर्ट कार्यालयों और मिशनों के बीच संवर्धित संपर्क • पासपोर्ट और वीजा के लिए आवेदन-पत्रों का शीघ्र निपटारा • रिकार्डों का सक्षम तरीके से रख-रखाव और कोंसली रिकार्डों की खोज • आवेदकों के लिए सेवाओं की संवर्धित क्षमता	एक वर्ष	छोटे मिशनों के उनके अपने प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत कंप्यूटरीकरण होने से मंत्रालय सभी मिशनों में लगभग 90 प्रतिशत कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
3.	प्रशिक्षण (भारतीय विदेश सेवा संस्थान)	• विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना • भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना • विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करना • विदेश मंत्रालय से इतर अधिकारियों, राजनयिक सदृश आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना		7.35	निम्नलिखित का आयोजनः • विदेशी राजनयिकों के लिए 3 व्यावसायिक पाठ्यक्रम • भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए वर्ष भर का प्रशिक्षण • विदेश मंत्रालय के सहायकों/लिपिकों/ अनुभाग अधिकारियों/अवर-सचिवों के लिए 10-12 पाठ्यक्रम • राजनयिक सदृश, विदेश मंत्रालय से इतर अधिकारियों आदि के लिए 3-4 पाठ्यक्रम	• भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजनीति, भारत की विदेशी और सुरक्षा नीति, अर्थव्यवस्था आदि तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनय के विभिन्न पहलुओं के प्रति भी विदेशी राजनयिकों को क्षमता प्रदर्शन का अवसर मिलना • भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए सेवा में प्रवेश हेतु बृहत् प्रशिक्षण • विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए शासन, कांसुली, लेखा, वाणिज्यिक कार्य के संबंध में प्रशिक्षण। • राजनीतिक कार्यक्षेत्रों में अवर सचिवों (भारतीय विदेश सेवा-(ख) के लिए प्रशिक्षण। • राजनयिक सदृश और विदेश मंत्रालय से इतर अधिकारियों को भारतीय विदेश नीति से परिचित कराना	एक वर्ष (चल रहा कार्यक्रम)	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
4.	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक			5.10				
	सार्क शिखर सम्मेलन				अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में सार्क शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी	सार्क समुदाय के साथ घनिष्ठ एकीकरण	अप्रैल 2007	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
5.	अन्य व्यय			106.3				
	(i) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को सहायता अनुदान	सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और सेमिनारों में प्रतिभागिता, प्रकाशन, छात्रवृत्तियां प्रस्तावित करने, विदेश में भारत महोत्सव के आयोजन आदि के जरिए सांस्कृतिक राजनय ("साफ्ट पावर")		70.00	• विदेश में भारत के 9 महोत्सव • भारत में 6 सांस्कृतिक महोत्सव • विदेश में 20 प्रदर्शनियां और बाहर से आने वाली 6 प्रदर्शनियां • 14 देशों में नृत्य, संगीत, हिंदी आदि में विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति • विदेशी छात्रों के लिए 1300 छात्रवृत्तियां • 25 विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी और देश से बाहर जाने वाले 90 सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल • विदेश में तीन सेमीनार और भारत में चार • विदेश से भारत में 130 यात्राएं और देश से बाहर विशिष्ट व्यक्तियों का जाना • काठमांडू, ढाका, काबुल, बीजिंग और वाशिंगटन में नए सांस्कृतिक केन्द्र खोले जाएंगे • अप्रैल 2007 में सार्क से संबंधित सांस्कृतिक गतिविधियां • विदेश में भारतीय नेताओं की अर्ध प्रतिमाएं भेजने के लिए 19 प्रस्ताव • भारत में 40 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए समर्थन • 5 नए पीठों की स्थापना • भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलना	• विदेश में भारतीय संस्कृति का संवर्धन और अन्य देशों को अपनी संस्कृति के प्रदर्शन के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराना • सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थाओं से सहयोग के लिए सूचना प्राप्त करना • सेमिनारों के जरिए नीति निरूपण के लिए प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करके द्विपक्षीय वार्ताओं से सूचना प्राप्त करना	एक वर्ष	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया /समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
5.	अन्य व्यय (जारी)			106.3				
	(ii) विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) हेतु सहायता अनुदान	आर्थिक सहयोग, पर वैश्विक मामलों के संबंध में अनुसंधान, विकासशील देशों में द्विपक्षीय वार्ता, बहुपक्षीय मंचों, सम्मेलनों और सेमिनारों, प्रकाशनों आदि में भागीदारी		1.75	• दक्षिण एशियाई विकास और सहयोग रिपोर्ट 2006 की तैयारी। • आर्थिक सहयोग पर 23 सेमिनारों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं की मेजबानी	अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और नीतिगत मामलों पर परामर्शी सूचनाएं प्रदान करना	एक वर्ष	
	(iii) भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के लिए सहायता अनुदान	भारत में सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना		2.40	• 60वें वार्षिक एशियाइ संबंध सम्मेलन का स्मरणोत्सव • अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर 5 सेमिनारों का आयोजन • यात्रा पर आने वाले विदेशी महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा 4 व्याख्यान		एक वर्ष	
	(iv) अन्य विविध मदें	संस्थाओं को अनुदान, विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए निधि • संयुक्त राष्ट्र सेवा संस्थान-संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल (यूएसआई)		35.98 1.38	वर्ष के दौरान सम्मेलनों/बैठकों तथा आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यकलापों में भागीदारी	संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में सहयोग	एक वर्ष (सतत् प्रयास)	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
5	अन्य विविध मदें (जारी)	• भारत चीन और भारत पूर्वी एशिया के विशिष्ट व्यक्तियों का यात्रा कार्यक्रम • चीनी अध्ययन संस्थान • भारत संयुक्त राज्य अमरीका विशिष्ट व्यक्तियों का यात्रा कार्यक्रम • भारत-फ्रांस मंच • भारत यूके गोलमेज • भारत यूरोपीय संघ गोलमेज • विदेश स्थिति मिशनों के जरिए हिन्दी का प्रचार-प्रसार		0.15 0.13 0.15 0.30 0.50 0.56 6.60	वर्ष के दौरान सम्मेलनों/बैठकों तथा आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यकलापों में भागीदारी न्यूयार्क में 13-15 जुलाई 2007 तक 8वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन विदेशों में भारतीय समाज और भारतीय मिशनों/केन्द्रों के लिए हिन्दी पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद 3 क्षेत्रीय हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन • विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों द्वारा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाना • हिन्दी की संवर्धन स्कीमों के लिए 35 मिशनों/केन्द्रों के लिए अनुदान और आपूर्तियां	गैर सरकारी संगठनों में भागीदारी के जरिए द्विपक्षीय संबंधों पर बेहतर समझबूझ का संवर्धन विश्व स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना	एक वर्ष	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग i) बंगलादेश	• आईटी पाठ्यक्रमों में अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना • कल्याणकारी कार्यक्रम • संस्थाओं/ऐतिहासिक भवनों आदि की मरम्मत/नवीनीकरण		15.00 1.50 0.56 12.5	• बुनियादी आईटी कौशल में 375 अध्यापकों को प्रशिक्षण • मुक्तियोद्धाओं के परिवारों को 66 छात्रवृत्तियां • 8 संस्थाओं/भवनों का निर्माण/मरम्मत/ नवीकरण *	भारत के प्रति बंगलादेश के लोगों में सदाशयता बनाना	प्रत्याशित गतिविधियां 1-4 वर्षों में पूरी होंगी	

टिप्पणी:

1. 600 बंगलादेशी राष्ट्रिकों को बुनियादी सूचना प्रौद्योगिकी कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि बंगलादेश में सूचना-प्रौद्योगिकी साक्षरता का प्रसार हो और नौकरियों की संभावनाओं में वृद्धि हो जिससे भारत में बंगलादेशियों के भारत में अवैध अप्रवासन पर रोक लगेगी।
2. बंगलादेश के मुक्तियोद्धाओं (स्वतंत्रता सेनानी), भारत के पक्षधर हैं, के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का समर्थन जिसमें स्नातक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना शामिल है तथा इनके समर्थन में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों का समर्थन किया जाना भी शामिल है।
3. * गाँधी आश्रम न्यास मुक्ति युद्ध संग्रहालय जैसी संस्थाओं/ऐतिहासिक भवनों की मरम्मत/नवीकरण, गोपाल गंज जिले में शैक्षिक सुविधाओं, ढाका विश्वविद्यालय सीनेट हाल के लिए सहायता, धमराई मंदिर पर नए 'रथ' का निर्माण, ओराकांडी ठाकुरवाड़ी, मानव कल्याण अनाथालय और कालीमठ देवी न्यास आदि के नवीकरण में सहायता की परिकल्पना की गई है ताकि भारत के महत्वपूर्ण पड़ोसी देश, जिसके पूर्व में और पूर्वोत्तर भारत में 5 राज्यों की साझी सीमा है, एक मुक्त/सहनशील प्रवृत्ति/राज्य व्यवस्था कायम रह सके।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ii) भूटान		290.91 (योजना 186.30 आग्रिम 104.60)	480.00				
		महा परियोजनाओं का निर्माण/प्रारंभ • 1020 मेगावाट ताला जल विद्युत परियोजना	141.50		परियोजना का पूर्ण प्रारंभ-भारत 1020 मेगावाट बिजली प्राप्त करेगा।	• भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध, सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार होगा	जुलाई 2006 में वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होगा, 31 मार्च 2007 तक पूरी तरह से प्रारंभ हो जाएगा।	यदि छठा यूनिट उपस्कर समय पर प्रदत्त नहीं किया जाता है तो इसके पूरी तरह से प्रारंभ होने में विलंब हो सकता है।
		डुंगसुम सीमेंट संयंत्र	55.00		कार्य का पूरा होना संयंत्र तक जाने वाली सड़क से जुड़ा हुआ है।	सीमेंट की उपलब्धता, द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन	कार्य के प्रारंभ होने की तारीख से 27 महीने	निर्माण पूर्व गतिविधियां अर्थात सड़क निर्माण शुरू किया गया है। भूटान सरकार और एक प्राइवेट कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में परियोजना की रूपरेखा को औद्योगिक विकास विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ii) भूटान (जारी)							
		पुनातसांगचू-1 जल विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	1.66		डीपीआर के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा	1100 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी	डीपीआर की जाँच और अनुमोदन 2007 के अन्त तक प्राप्त किया जाएगा।	**वापकोस लि.** को डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शक के रूप में लगाया गया था
		पुनातसांगचू-1 जल विद्युत परियोजना • निर्माण-पूर्व • वास्तविक परियोजना	12.75 80.00		2 पुल और एक सड़क के लिए निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।	सस्ती और स्वच्छ विद्युत उपलब्ध होगी	परियोजना 8 वर्ष में पूरी होगी	
		विकास सब्सिडी		105	भूटान में विकास को बढ़ावा मिलेगा	भूटान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे	वार्षिक विकास सहायता	भूटान को बजटीय सहायता
		चुखा सब्सिडी		85	पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा कम दर पर बिजली की आपूर्ति; मात्रा विद्युत के वास्तविक ग्रहण पर निर्भर करेगी	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड एवं दामोदर घाटी निगम को कम दर पर विद्युत आपूर्ति	एक वर्ष	इस सब्सिडी को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ii) भूटान(जारी)	अन्य स्कीम						
		भूटान को सुपर किरोसिन ऑयल और एलपीजी की सब्सिडी युक्त कीमत पर आपूर्ति		30	भूटान में किरोसिन और एलपीजी के लिए मात्रा, निर्धारित कोटा के अन्दर माँग पर निर्भर करेगी	भारत-भूटान सीमा पार एसकेओ/एलपीजी की तस्करी रूकेगी और यह भूटान के साथ हमारी विकास भागीदारी का एक घटक है	एसकेओ/ एलपीजी की वार्षिक आपूर्ति	अन्तर्राष्ट्रीय साम्य कीमत में वृद्धि होने से सब्सिडी में वृद्धि करना पड़ेगा
		उत्पाद शुक्ल वापसी		65	भूटान द्वारा भारत को वर्ष 2003-04 के लिए उत्पाद शुल्क वापसी का दावा होगा	मुक्त व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय निर्यात का संवर्धन और भूटान की राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	निरन्तर सहायता कार्यक्रम	यह वास्तविक व्यापार पर निर्भर करेगा। राजस्व विभाग द्वारा परिकलित आकड़े

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ii) भूटान(जारी)	परियोजना से जुड़ी सहायता		255.11	कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं	सहायता, भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए और भूटान के साथ हमारे विकास सहयोग के अनुरूप है	परियोजनाएं, भूटान की नौवीं पंचवर्षीय योजना (2002-08) के लिए भारत की सहायता की भाग हैं। अधिकांश परियोजनाएं जून 2008 तक पूरी होने वाली हैं	
		सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सहायता • राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए प्रशासन भवन का निर्माण		0.54	अधिकांश सिविल कार्य सभी परियोजनाओं के लिए पूरे हो जाएंगे	भूटान के सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास में सहायता	जून 2007	
		• आरएपीए के लिए प्रशासन भवन का निर्माण		0.10			जून 2007	
		• राष्ट्रीय संग्रहालय, पारो के लिए कार्यालय/ प्रदर्शनी हाल का निर्माण		0.57			भूटान की 10वीं पंचवर्षीय योजना (2008-2013) में आगे ले जाया जाएगा	
		• सेमथोका झांग का नवीकरण		4.89			दिसम्बर 07	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ii) भूटान (जारी)	**शिक्षा का संवर्धन** -नए विद्यालयों का निर्माण		13.42	10 विद्यालय पूरे किए जाएंगे	भूटान में सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना	6 विद्यालय जुलाई 2007 तक पूरे किए जाएंगे। शेष दिसम्बर 2007 तक पूरे किए जाएंगे	
		-शेरूब्से कॉलेज का विस्तार		0.95			अगस्त 2007	
		विद्युत अवसंरचना का विकास • पुनातसांग्चू 2 (992 मेगावाट) और मांगदेचू एचपीपी (670 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट		5.95	डीपीआर की तैयारी	भूटान में पुनातसांग्चू-II एचईपी (992 मेगावाट) और मांगदेचू एचईपी (670 मोगावाट) के विकास की जाँच करना	डीपीआर का मसौदा सितम्बर 2008 तक पूरा हो जाएगा।	पुनातसांग्चू-II के लिए डीपीआर हेतु वापकोस को लगाया गया है और मांगदेचू के लिए डीपीआर हेतु एनएचपीसी को लगाया गया है
		• एकीकृत ऊर्जा मास्टर योजना			ऊर्जा मास्टर योजना की तैयारी			
		• देवथांग-रांगिया ट्रांसमिशन लाइन		15.00	60 किमी. ट्रांसमिशन लाइन	भारत की सहायता से निर्मित जल विद्युत संयंत्र से बिजली लेने के लिए ट्रांशमिशन लाइन का निर्माण	परियोजना नवम्बर 2007 तक पूरी हो जाएगी।	मई 2006 में ठेका दिया गया था

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ii) भूटान (जारी)	• तिंतबी-ट्रांगसा-बुमथांग ट्रांशमिशन लाइन		25.00	74 किमी. ट्रांशमिशन लाइन		परियोजना मई 2008 तक पूरी होगी	मई 2006 और जुलाई 2006 में ठेके दिए गए थे।
		स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना • जेडीडब्ल्यूएनआर अस्पताल थिंपू का निर्माण • मोंगर रिजनल रेफरल अस्पताल मोंगर का निर्माण		15.00 6.70	थिंपू में 350 विस्तरों वाला अस्पताल और मोंगर में 150 विस्तरों वाला अस्पताल	भूटान के थिंपू और अन्य इलाकों में उम्दा चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करना। स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में सहायता	निर्माण जून 2007 तक पूरा हो जाएगा जून 2007	
		शहरी विकास के लिए सहायता • निम्न आय वाले भवन का निर्माण • हा टाउन में शहरी विकास		4.52 1.50	300 से अधिक मकान बनाए जाएंगे भारतीय विशेषज्ञ योजनाओं को अंतिम रूप देंगे	भूटान में शहरी विकास में सहायता	निर्माण जून 2008 तक पूरा हो जाएगा भूटान की 10वीं पंचवर्षीय योजना (2008-2013) में ले जाया जाएगा।	

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ii) भूटान (जारी)							
		पुलों और सड़कों का विकास						
		• जिलपोसिंग-न्गानग्लम रोड		10.00	25 किमी. सड़क और तीन पुल	भूटान के अवसंरचना और सड़क नेटवर्क के विकास में सहायता करना	परियोजना अप्रैल 2008 तक पूरी होगी	
		• बबेसा फुंटसोलिंग राजमार्ग को दो लेन का बनाना		40.00	प्रथम चरण पूरा किया जाना है और दूसरा चरण आरंभ किया जाना है		यह परियोजना भूटान की 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी होगी (2008-2013)।	162 किमी. में से 114 किमी. को दो लेन का बनाना है (दामचू से चूखा तक 48 किमी. खण्ड को छोड़कर)
		• चुनजोम-पारो हवाई अड्डा राजमार्ग को दो लेन का बनाना		14.91	पारो हवाई अड्डे से थिंपू तक 18.45 किमी. सड़क		यह परियोजना दिसम्बर 2008 तक पूरी हो जाएगी।	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग ii) भूटान (जारी)	**व्यापार तथा उद्योग संवर्धन** • अर्क तेल - गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, थिम्पू		0.50	सिविल कार्य पूर्ण किए	भूटान में व्यापार और उद्योग सुविधा	सितम्बर 2007	
		उन्नत मीडिया आधार-संरचना • थिम्पू में टी.वी. सेन्टर का निर्माण		2.13	टी.वी. सेन्टर का कार्य समाप्त करना और उपस्करों की आपूर्ति	उन्नत मीडिया कवरेज	जून, 2007	
		युवा विकास संवर्धन • थिम्पू के युवा विकास केन्द्र की स्थापना • 'रिन्यू' प्रोजेक्ट, थिम्पू		1.99 2.66	युवा विकास केन्द्र और 'रिन्यू' में सिविल कार्यों को समाप्त करना	युवा विकास का संवर्धन और एनजीओ के साथ सहयोग	जून, 2008 भूटान की 10वीं पंचवर्षीय योजना (2008-2013) का शेष।	
		कोर्ट निर्माण सर्वोच्च न्यायालय इमारत, थिम्पू		21.95	आरेखन इत्यादि की तैयारी	भूटान के सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण	भूटान की 10वीं पंचवर्षीय योजना (2008-2013) का शेष।	योजना की तैयारी चल रही है।

टिप्पणियाँ-

1. गैर-योजना परिव्यय चुखा जल-विद्युत परियोजना से खरीदी गई विद्युत की लागत को राज सहायता; भारतीय तेल निगम से भूटान द्वारा खरीदी गई तेल और एलपीजी की लागत को राज सहायता, भूटान द्वारा भारत से खरीदे गए उत्पादों की खरीद पर भुगतान की गई सीमा शुल्क की वापसी के लिए, भूटान की नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, स्वास्थ्य, आधार संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, आईटी, मानव संसाधन विकास, नागरिक उड्डयन, मीडिया, सड़क तथा पुल, विद्युत इत्यादि जैसे विविध क्षेत्रों में कई सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए परियोजनाबद्ध सहायता प्रदान करेगा। यह भूटान के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता देगा और भूटान को स्थायित्व की ओर ले जाएगा।
2. भूटान के साथ द्विपक्षीय वचनबद्धताओं से भारत के लिए राजनैतिक सद्भावना उत्पन्न होगी। भूटान से राहत दर पर विद्युत की खरीद से भारतीय विद्युत की मांग-आपूर्ति का अन्तराल कम होगा, जबकि भूटान को पर्याप्त राजस्व देगा। सीमा शुल्क की वापसी से भारतीय निर्यातों को भी संवर्धन प्राप्त होगा।
3. भूटान परियोजना के योजना परिव्यय 186.31 करोड़ रुपए, 104.60 करोड़ रुपए के ऋण के भाग के अतिरिक्त है।
4. भूटान को कुल प्रक्षेपित गैर-योजना सहायता 728.39 करोड़ रुपए है, जबकि परिव्यय 480.00 करोड़ रुपए है; अतिरिक्त अपेक्षाएँ संशोधित आकलन के स्तर पर मांगी गई हैं।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग iii) नेपाल		38.00	100.00				
		• लघु विकास परियोजना (एसडीपी) योजना, जिसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक वानिकी, महिला एवं शिशु संबंधी मामले इत्यादि के क्षेत्र में स्थानीय निकायों, एनजीओ द्वारा परियोजनाएं ली गई हैं।		35.00	3 करोड़ नेपाली रूपए से कम के लघु दर्जे की परियोजनाओं के द्वारा आधारभूत संरचना क्षेत्रों, नामतः शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदाय विकास, संचार और सड़क/पुलों का निर्माण परियोजनाओं की संख्याः स्वास्थ्यः 25 शिक्षाः 75 समुदाय विकासः 20	नेपाल में सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, नेपाल में आधार-संरचना विकास और नेपाल के लोगों में भारत के लिए सद्भावना	परियोजना की अवधि 18-24 माह	नेपाल में राजनीतिक गतिविधियां
		विद्युत आपूर्ति (एनएचपीसी) को भुगतान		8.5	टनकपुर जल विद्युत परियोजना से नेपाल को विद्युत की आपूर्ति		वार्षिक भुगतान	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग iii) नेपाल (जारी)	• सीमा जाँच चौकियां (रक्सौल-बीरगंज, जोगवानी-विराटनगर, सुनौली-भैरहवा और नेपाल गंज-नेपाल गंज मार्ग तथा नक्सलवाड़ी-काकारबित्ता से होकर पानीटंकी) में ऐसी चौकियों के उन्नत प्रशासन के लिए आधारभूत विकास	20.00		4 जांच चौकियों का विकास/ वर्ष 2007-08 में एनएचएआई द्वारा केवल रक्सौल-बीरगंज में कार्य किया जाएगा	• सीमा व्यापार, सीमा सुरक्षा बढ़ाने खुली सीमा के अनुचित प्रयोग की रोकथाम, सीमा व्यापार के उत्तम विनियमन की रूकावटों का समाधान	रक्सौल-जाँच वीरगंज चौकी के लिए 2 वर्ष; अन्य जाँच चौकियां प्राथमिकता-II पर है और उनकी समय सीमा अभी निर्धारित करनी है	नेपाल में राजनीतिक गतिविधियां
		• नेपाली छात्रों को छात्रवृत्ति		7. 0	विभिन्न विषयों में 282 छात्र-वृत्तियां भारत में और 1000 नेपाल में	नेपाल के मानव-संसाधन विकास में सहायता	एक वर्ष	आईसीसीआर द्वारा कार्यान्वयन
		• बीर अस्पताल का विस्तार		40.0	काठमान्डू 200 बिस्तरों वाले आपातकालीन अस्पताल सह मानसिक आघात केन्द्र की स्थापना	उच्च गुणवत्ता चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना	18 माह	सितम्बर 2006 में कॉन्ट्रेक्ट दिया गया

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग iii) नेपाल (जारी)	• मनमोहन अधिकारी पॉलिटेक्निक		8.00	13079.28 वर्गमीटर के कुल क्षेत्र के पॉलिटेक्निक की स्थापना जिसमें इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल और मकैनिकल के विषय हैं	• तराई क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दक्ष कार्मिकों की व्यवस्था करना	सिविल निर्माण 2007 तक पूरी हो जाएगी	नेपाल में राजनैतिक गतिविधियां
		• महेन्द्र नगर- टनकपुर मार्ग		20.00	पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के टनकपुर बैराज से लगभग 13.5 किमी. मार्ग का निर्माण	• सीमा सम्पर्क बढ़ाना, भारत सरकार की वचनबद्धता को पूरा करना	2 वर्ष	
		• देवीघाट जल-विद्युत परियोजना		10.0	बीएचईएल द्वारा प्रतिस्थापन अपग्रेडेशन कार्य	नेपाल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए (लगभग 14.2 मेगावाट) अतिरिक्त विद्युत	लगभग 2 वर्ष	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग iii) नेपाल (जारी)	• नौमूरे भंडारण-सह-जल विद्युत परियोजना (लगभग 240 मेगावाट)	3.00		भंडारण सह जल विद्युत केंद्र की स्थापना	• कम पानी के मौसम में उत्तर प्रदेश के लिए राप्ती में जल के प्रवाह की अधः धारा को बनाए रखना और विद्युत का उत्पादन	अभी निर्णय लिया जाना है	नेपाल में राजनैतिक गतिविधियां
		• सीमा-पार पांच रेल संपर्कों का क्रियान्वयन- नामतः कटिहार-जोगबनी, गोंडा- नेपालगंज, नौतनवा-भैरहवा, नई जलपाईगुड़ी-पानीटंकी, जयनगर बीजलपुरा	7.00		डीपीआर तैयारी जारी	सीमा-पार संपर्क और व्यापार का संवर्धन करने के लिए	अभी निर्णय लिया जाना है	डीपीआर की तैयारी चल रही है।
		• तराई क्षेत्र में सड़क संरचना का विकास	8.00		पहले चरण के लिए डीपीआर की तैयारी इसमें 552 कि.मी. लंबी 22 सड़कों का विकास, 14 पुलों का निर्माण शामिल है	तराई क्षेत्र में ढांचे का विकास	सितंबर, 2007 तक	

नेपाल को सहायता के लिए 100 करोड़ रू. का गैर योजना परिव्यय तथापि, संशोधित अनुमान के स्तर पर 28.5 करोड़ अतिरिक्त मांगा जाएगा।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग iv) श्रीलंका			28.00				परियोजनाओं का क्रियान्वयन श्रीलंका में परिस्थितियाँ शांतिपूर्ण होने तथा उनके सहयोग के अध्यधीन है।
		रक्षा प्रशिक्षण		30.00	श्रीलंका ने 2500 स्लाट रक्षा प्रशिक्षण के लिए और 700 पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का अनुरोध किया है	भारत के लिए सद्भावना और प्रभाव	निरंतर प्रक्रिया	
		लघु विकास एवं सुनामी राहत परियोजना		20.00	लघु समुदाय, विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन (मत्स्ययन नौकाओं तथा जालों की आपूर्ति)	स्थायी विकास उपलब्ध कराएगा	6 से 18 माह तक	भारत का हाई कमीशन, कोलंबो द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।
		स्वास्थ्य परियोजनाएं		21.72	त्रिनकोमाली बेस हॉस्पिटल का उन्नयन और डिकोया, श्रीलंका में 150 बिस्तर के हॉस्पिटल का निर्माण	श्रीलंका की चिकित्सा संस्थाओं को सहायता	2008	
		अवसंरचना परियोजनाएं			के.के. एस हार्बरका पुनः निर्माण	श्री लंका की बंदरगाह अवसंरचना को सहायता		

प्रस्तावित गैर योजना परिव्यय के लिए अतिरिक्त 43.72 करोड़ रू. संशोधन अनुमान के स्तर पर मांगा जाएगा।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग v) मालदीव			15.00 (कुल)				
		• मालदीव के रक्षा और पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण		3.50	100 रक्षा और पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण	भारत के लिए सामान्य सद्भावना और भारत के दीर्घकालिक हितों का संवर्धन	निरंतर प्रक्रिया	
		• असैनिक पाठ्यक्रमों में मालदीव के कार्मिकों को प्रशिक्षण		0.70	20 असैनिक कार्मिकों को प्रशिक्षण		निरंतर प्रक्रिया	
		• जल विज्ञान सर्वेक्षण एकक की स्थापना		2.74	जल विज्ञान सर्वेक्षण एकक की स्थापना को पूर्ण करना		2007 में पूर्ण होने की आशा है।	
		• मेजबानी और पर्यटन अध्ययन संकाय की स्थापना		25.40	निर्माण प्रारंभ होना है, उपकरणों की आपूर्ति और मालदीव के कार्मिकों को प्रशिक्षण	मालदीव में मेजबानी के क्षेत्र में सहायता	18 माह	
		• इन्सैट मौसम विज्ञानी आंकड़ों की प्राप्ति का उन्नयन		0.22	मौसम विज्ञानीय आंकड़ा प्राप्ति का उन्नयन	चक्रवातों और अन्य जलवायु परिवर्तनों की अग्रिम चेतावनी को सुसाध्य बनाना		

प्रस्तावित गैरयोजना परिव्यय के लिए संशोधित अनुमान के स्तर पर 17.56 करोड़ रूपए की मांग की जाएगी।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग vi) म्यांमा		40.41	40.00				
		• तामू-कलेम्यो-कलेवा रोड का निर्माण/रखरखाव और 160 कि.मि. लंबे तामू-कलेम्यो-कलेवा रोड दैनंदिन निर्माण		31.86	• सड़क के एक भाग को पुनः समतल बनाना। • बेकार पड़े पुलों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करना। • 160 कि.मि. सड़कों का दैनंदिन रखरखाव	बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क संपर्क का सुधार, सीमा पार व्यापार और पर्यटन, विद्रोह, हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और अन्य समस्याओं के नियंत्रण को सुसाध्य बनाना।	2007-08	सीमा सड़क संगठन समतल किए जाने वाले भाग और मरम्मत किए जाने वाले पुलों की संख्या का अनुमान लगा रहा है।
		• दूर-संवेदन में सहयोग		3.00	• आई आर एस पी-5 आरआईआरएसपी-6 उपग्रहों से म्यामां को आंकड़े उपलब्ध कराना।	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग संवर्धन, भारत के लिए सद्भावना और प्रभाव पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महत्वपूर्ण एजेंसी बनने में इसरो की सहायता करना।	2008-09	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग vi) म्यामां(जारी)	• म्यामां में ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन का उन्नयन		4.7	• रिसोर्सैट-। और कार्टोसैट डाटा प्रसंस्करण सुविधाओं का उन्नयन।	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन और भारत के लिए सद्भावना सृजन	2007-08	
		• सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजनाएं		13.5	• यांगोन और मांडले दो ई-शिक्षण केन्द्रों की स्थापना	भारत और म्यामां के बीच संबंधों का संवर्धन	5 वर्षों में पूरा किया जाना है।	
		• कालादम बहु-विध पारगमन परियोजना प्रणाली	40.41		• सितवे और कलेतवा के बीच 179 कि.मी. राजमार्ग पर सितवे बंदरगाह अंतर्देशीय जल मार्ग प्रणाली पर टर्मिनल का निर्माण आरंभ।	उत्तर-पूर्व के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना	5 वर्षों में पूरा किया जाना है।	बंदरगाह, जलमार्ग और सड़क का विकास किया जाना है।
		• शैक्षिक-सांस्कृतिक और अन्य सहयोग		2.0		म्यामां में क्षमता निर्माण को बढ़ावा और सद्भावना सृजन।	एक वर्ष	

प्रस्तावित गैर-योजना परिव्यय में संशोधित अनुमान के स्तर पर 15.06 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे जाएंगे।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	vii) अन्य विकासशील देश			420.55 (कुल)				
		अफगानिस्तानः	130.68	342.87	पारेषण लाइन की लम्बाई 202 किमी. और टावरों की संख्या 600.	अवसंरचना का विकास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और लाभार्थी देशों में सद्भावना संवर्धन	अक्तूबर, 2008	परियोजना निर्धारित समयावधि से चार माह आगे चल रही है।
		• पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220 के वी डबल सर्किट पारेषण लाइन और काबुल में उप-स्टेशन का निर्माण						
		• स्कूलों के लिए खाद्य सहायता कार्यक्रम		200.00	22000 टन उच्च प्रोटीन बिस्कुटों की आपूर्ति		सितम्बर, 2007	डब्ल्यू एफ पी के जरिए आपूर्तियाँ की जाती हैं।
		• जरांग से डेलाराम तक सड़क का निर्माण			कुल 218 किमी. सिविल कार्य में 75% पूर्ण।	भू-अवरुद्ध अफगानिस्तान का समुद्र के जरिए इरान से संपर्कों में वृद्धि	मार्च, 2008	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	vii) अन्य विकासशील देश	**अफगानिस्तानः** (जारी)						
		• हेरात प्रांत में सलमा बांध बिजली परियोजना (42 मेगावाट) का पुनर्निर्माण और इसका पूरा होना।		195.00	कुल कार्य के 60% का पूरा होना	बिजली अवसंरचना के लिए अफगानिस्तान सरकार को सहायता	जनवरी, 2009	
		• इंदिरा गाँधी बाल स्वास्थ्य संस्थान का पुनर्निर्माण		20.00	पॉलीक्लीनिक, नैदानिक केन्द्र और पुस्तकालय का कार्य पूरा होना	बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता	दिसम्बर, 2007	
		• विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए अफगानी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ		15.00	500 छात्रवृत्तियों का आबंटन	सद्भावना संवर्धन और क्षमता निर्माण	2011 तक प्रतिवर्ष	

टिप्पणीः अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण और अन्य पुनर्निर्माण/पुनर्वास/विकास परियोजनाएं भी चलायी जा रही हैं।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	vii) अन्य विकासशील देश (जारी)	पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों को द्विपक्षीय सहायताः						
		• नई दिल्ली में फिलीस्तीन दूतावास का निर्माण		7.00	निर्माण का आरंभ	फिलीस्तीनी प्राधिकारियों को सहायता और अवसंरचना निर्माण	2008-09	
		• फिलीस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकार में अवसंरचना विकास		12.00	अबूदिस में स्कूलों और गाजा तथा दक्षिणी सूडान में अस्पतालों के निर्माण में सहायता शिक्षा के लिए यूनीसेफ को दान	स्कूल और अस्पताल का निर्माण आरंभ करना	अप्रैल 2010	क्षेत्र की कठिन परिस्थितियाँ
		• ईराक को पुनर्वास और राहत सहायता		5.00	शिक्षा के लिए यूनीसेफ को दान	मानवीय सहायता के जरिए ईराकी जनता को समर्थन देना	एक वर्ष	क्षेत्र की कठिन परिस्थितियाँ
				11.20	स्कूल में भोजन कार्यक्रम के लिए फोर्टिफॉयड बिस्कुटों का दान	कौशल उन्नयन	एक वर्ष	
				1.25	एनआईआईटी द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण		एक वर्ष	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	vii) अन्य विकासशील देश (जारी)	• हवाना, क्यूबा में आईटी केन्द्र की स्थापना		0.96	• 400 छात्रों का प्रशिक्षण • परियोजना के लिए आपूर्तियां और परामर्श	द्विपक्षीय संबंधों में सुधार। स्थानीय लोगों के कौशल में वृद्धि	वर्ष 2005 तक पूरा किया जाना है।	
		• जिम्बाब्वे में एसएमई क्षेत्र का विकास		10.00	• 90 कार्य माहों के लिए 19 कार्मिकों का प्रशिक्षण	द्विपक्षीय संबंधों में सुधार, स्थानीय लघु और मंझोले उद्योगों का विकास।	2007-09	
		• भारत लाओस द्विपक्षीय आईसीटी सहयोग		2.20	• भारत में 30 छात्रों का एमसीए का प्रशिक्षण	लाओस के लिए मानव संसाधन क्षमता और भारत के लिए सद्भावना का सृजन	3 वर्ष	
		• हनोई, वियतनाम में आईसीटी के उच्च संसाधन केन्द्रों की स्थापना		9.50	• आईटी से जुड़ी प्रयोगशालाओं की स्थापना		1 वर्ष	

टिप्पणीः

1. वायुसेना अकादमी की स्थापना के लिए लाओस लोकतांत्रिक जन-गणराज्य को सहायता अनुदान (4.5 करोड़ रुपए) का विचार है। वियतनाम, कम्बोडिया, फिजी और नौरू को तकनीकी सहायता और सहायता अनुदान देने का भी प्रस्ताव है।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	viii) अफ्रीकी देशों को सहायता			50.00				
		पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकाः						
		• मेडागास्कर में इंटरनेट नेटवर्क की स्थापना		17.00	राष्ट्रपति कार्यालय में सुरक्षित नेटवर्क की स्थापना	आईटी अवसंरचना में सुधार में सहायता। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों के लोगों में भारत के प्रति सद्भावना सृजन	समय-सीमा सहित परियोजना के अन्य ब्यौरों पर कार्य किया जा रहा है	
		• तंजानियाँ और शेसल्स में सूचना सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों का निर्माण		15.00	आईटी केन्द्रों की स्थापना		3 वर्ष	
		• कोमोरोस में कंवेशन सेंटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण		5.0 0	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	भारत के लिए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराना	3 वर्ष	
		• अन्य सहायता		10.00	इस क्षेत्र के देशों को दवाओं, ट्रैक्टरों, कृषि उपकरणों इत्यादि की आपूर्ति	पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लोगों में भारत के लिए सद्भावना का सृजन	1 वर्ष	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	viii) अफ्रीकी देशों को सहायता (जारी)	पश्चिमी अफ्रीकाः • पैन अफ्रीकी टेलिमेडिसिन तथा टेलि-एजुकेशन ई-नेटवर्क		130.44	हब स्टेशन को पूर्ण और चरण प्रथम शुरू होना है।	हमारी प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने, अफ्रीका को चिकित्सकीय एवं शिक्षा सहायता प्रदान करने।	5 वर्ष	मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।
		• कोड डी आयवरी में कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना		5.0				
		• ऊर्जा आधारित विकास कार्यक्रम		5.0	• वापकोस द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन	पश्चिमी अफ्रीका के देशों के लोगों के बीच भारत के प्रति सद्भावना का सृजन करना	एक वर्ष	
		• पश्चिमी अफ्रीका में कृषि संबंधी परियोजना		5.0	• बुर्किनाफासो में परियोजना स्थापित करना		एक वर्ष	
		• शैक्षणिक सामग्री/कंप्यूटर/ प्रयोगशाला उपकरणों को भेंटस्वरूप देना		7.0	• चाड, बेनिन, कैमरून, नाइजर, इक्वाटोरियल गिनिया, साओटोम एवं प्रिंसिपे, गाबोन, लाइबेरिया को सहायता प्रदान करना		एक वर्ष	
		• नेशनल पोस्ट आफिस का निर्माण एवं सुसज्जीकरण।		5.0			एक वर्ष	
		• चिकित्सा सहायता और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रावधान		16.00	• 7 देश	भारत के लिए व्यवसाय के अवसर प्रदान करना।	एक वर्ष	
		• सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजना		16.50	• 3 देश		एक वर्ष	

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग ix) मध्य एशिया को सहायता	मध्य एशियाई देशों के कामिकों को भारत में सैन्य प्रशिक्षण • **उजबेकिस्तानः** • उद्यमशीलता विकास केन्द्र की स्थापना; • उपग्रह आधारित टेली-मेडिसिन, टेलि-एजुकेशन संपर्क; **तजाकिस्तानः** • लघु हाइडल विद्युत संयंत्र (वारजोब-I) का पुनर्वास • उपकरण कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र **आर्मेनियाः** • सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना		20.00 (कुल)	सैन्य प्रशिक्षण के लिए स्लाट प्रदान करना उद्यमशीलता विकास केन्द्र, उजबेकिस्तान स्थापित करना प्रशिक्षण केन्द्र, तजाकिस्तान स्थापित करना। सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, येरेवान वान स्थापित करना	सूचना प्रौद्योगिकी में दक्षता का संवर्धन। क्षेत्र का सामान्य विकास तथा मध्य एशिया के देशों के लोगों के बीच भारत के प्रति सद्भावना का सृजन भारत के लिए व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि		एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	vii) अन्य विकासशील देश (जारी)	**आइटेक कार्यक्रमः** • अन्य देशों के उम्मीदवारों को विभिन्न नागरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण		60.00	• भारतीय संस्थानों में नागरिक एवं रक्षा के 4000 सहभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।	156 आइटेक सहभागी देशों तथा सार्क देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का संवर्धन एवं इन्हें बेहतर बनाना।	एक वर्ष (सतत कार्यक्रम)	
		अफगानिस्तान कार्यक्रमः • अफगानिस्तान कार्यक्रम के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ		9.00	• अफगानिस्तान के 500 उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना	अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण की व्यवस्था करना तथा सद्भावना को बढ़ावा देना।	एक वर्ष	
		एस सी ए ए पी कार्यक्रमः		8.00	• अफ्रीका के राष्ट्रमंडल देशों के 600 नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।	अफ्रीका के राष्ट्रमंडल देशों को सुदृढ़ करना।		
		सार्क कार्यक्रमः		3.00	• सार्क की मंत्रिस्तरीय 5 बैठकों का आयोजन तथा अन्य कार्यकलाप करना।	सार्क सहयोग को सुदृढ़ करना।	एक वर्ष	भारत अप्रैल, 2007 में सार्क की अध्क्षता ग्रहण करेगा।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7	लोक निर्माण	भारत तथा विदेश में चांसरी और आवासीय भवनों का निर्माण		165.00	• विदेश स्थित 20 देशों में चांसरी और आवासीय भवनों का निर्माण • विदेश स्थित 4 देशों में तथा भारत में 1 भूखंड एवं निर्मित संपत्तियों का अधिग्रहण • विदेश भवन सहित भारत में कार्यालय और संस्थान भवनों के 4 परियोजनाओं का निर्माण	स्थायी आस्तियों का सृजन और इसके परिणामस्वरूप कुछ समय के पश्चात भारत सरकार की किराया देयताओं में कमी।	विभिन्न निर्माण परियोजनाएँ निर्माण/ निर्माण पूर्व प्रक्रिया के भिन्न-भिन्न चरणों में हैं और अगले तीन वित्त वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।	

टिप्पणीः

1. आबुजा, बहरीन, बीजिंग, ब्रासीलिया, दार-ए-सलाम, ढाका, काबुल, काठमांडू, मस्कट, पारामारिबो, पोर्ट लुई, ताशकंद, वारसा, दोहा, पोर्ट ऑफ स्पेन, टोक्यो, शंघाई, बर्लिन, प्राग, आईसीसीआर नई दिल्ली, आईसीसीआर कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू भवन नई दिल्ली में कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण/जोणोद्धार की परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं। लुओयांग में भारतीय शैली के बौद्ध धर्मस्थल का निर्माण जुलाई, 2007 तक पूरा होना है और बाली में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र का भी निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

2. नैरोबी, स्टाकहोम, जेनेवा, कोलम्बो और कोलकाता में सम्पत्ति (भूखंड/भवन) की खरीद करना परिकल्पित है।

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08 (करोड़ रूपए)		मात्रापरक वितरण/वास्तविक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय	टिप्पणी/जोखिम घटक
			योजना	गैर योजना				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8	आवासन	• विदेश में आवासों एवं भारत में रिहायशी क्वार्टरों/हॉस्टल का निर्माण • आवास के प्रयोजनों से विदेशों में सम्पत्तियों का अधिग्रहण • विदेशों में सम्पत्तियों का मरम्मत तथा पुनरुद्धार कार्य		85.00	• विदेश के 9 देशों में मिशनों/केन्द्रों के लिए आवासों का निर्माण करना। • भारत में आवासीय क्वार्टरों/हॉस्टल सूट का निर्माण करना। • विदेश में 1 देश में आवासीय प्रयोजनों के लिए सम्पत्तियों का अधिग्रहण करना। • विदेशों में सम्पत्तियों का मरम्मत तथा पुनरुद्धार करना।	• स्थायी आस्तियों का सृजन। • कुछ अवधि के उपरान्त भारत सरकार की किराया देयता में कमी।	विभिन्न निर्माण परियोजनाएँ निर्माण/निर्माण-पूर्व प्रक्रिया के भिन्न-भिन्न चरणों में है और अगले तीन वित्त वर्षों में पूर्ण हो जाने की आशा है।	

टिप्पणीः

1. इस्लामाबाद, लंदन, बैंकाक, सिडनी, बर्लिन, निकोसिया, सिंगापुर, टोक्यो और कीव में आवासीय भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के पुराने हॉस्टल में छह हॉस्टल सूटों के निर्माण का प्रस्ताव है। तेहरान में राजदूतावास आवास के लिए एक भवन का निर्माण भी विचाराधीन है।

***

अध्याय III – सुधार एवं नीतिगत पहल

विगत कई वर्षों में आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए, ऐसी सहायता देने के तौर-तरीकों में उत्तरोत्तर परिष्कार हुआ है । कुछ समय से विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों, आउटसोर्सिंग, पणधारियों की भागीदारी, व्यवहार्यता और मूल्यांकन अध्ययन इत्यादि की भूमिका बढ़ रही है । महत्वपूर्ण मौलिक सुधारों में से कुछ नीचे दिए गए हैं ।

प्रस्तावित भारत अंतरराट्रीय विकास प्राधिकरण, जो कि अन्य देशों को मदद और तकनीकी सहायता के लिए बेहतर प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए छत्र संगठन होगा, की स्थपना एक ऐतिहासिक कदम होगा । इससे कार्यक्रमों की आयोजना, परियोजनाओं का क्रियान्वयन, सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों और अभिकरणों के बीच तथा लाभग्राही सरकार के साथ भी समन्वय और हमारे प्रयासों के मूल्यांकन को सुसाध्य बनाने में अधिक क्षमता प्राप्त होगी जिससे भविष्य में बेहतर सुपर्दगी की हमारी क्षमता का संवर्धन होगा ।

परिणामों की सुपुर्दगी में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत की है । इसमें पासपोर्ट प्रणाली का कंप्यूटरीकरण और संयोजन, मिशनों के लिए मानकीकृत लेखा सॉफ्टवेयर और प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं । दैनंदिन संचार भी उत्तरोत्तर इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है । हमारे लेखों की पूरी तरह जांच की जा रही है, और अभिलेखों तथा ऐतिहासिक आंकड़ों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है । हमारे पुस्तकालय संसाधनों का विस्तार करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

प्रत्यायोजित शक्तियों में संवर्धन का प्रावधान करके मंत्रालय के कार्यकरण के विभन्न पहलुओं में कार्य संचालन को करगर बनाने और क्षमता का संवर्धन करने, कार्य की आउट सोर्सिंग, कंप्यूटरीकरण, व्यय की निगरानी, वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक सूचना के कई उपाय किए गए हैं । कुछ महत्वपूर्ण विषयों से संबधित सुधार नीचे दिए गए हैं ।

मूल्यांकन

परियोजना क्रियान्वयन का अनिवार्य अंग है - समुचित मूल्यांकन ताकि परियोजनाएं अपने निर्धारित उद्देश्यों को सक्षम और सार्थक ढंग से प्राप्त करें । विदेशों में हमारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सदैव वित्तीय तथा व्यवहार्यता शर्तों का अनुपालन किया जाता है ताकि देश के विकास संबंधी प्रयासों के लिए ठोस आधार बन सके । इसमें हमने परियोजना निगरानी तथा परवर्ती मूल्यांकन के लिए एक तंत्र विकसित किया है ।

मूल्यांकन इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं जिससे परियोजना तैयारी के स्तर पर जांच, क्रियान्वयन के स्तर पर निगरानी और पूरा हाने के बाद के स्तर पर उपलब्धि का विश्लेषण किया जाता है । इससे जो सीख मिलती है वह भविष्य के लिए सूचना का कार्य करती और इर इस प्रकार मूल्यांकन का एक चक्र तैयार होता है । उदाहररण के लिए आईटेक विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रशिक्षण

कार्यक्रमों के पाठयक्रमों की विषयवस्तु, प्रशिक्षण संस्थानों की बुनियादी संरचना में सुधार किए गए हैं ।

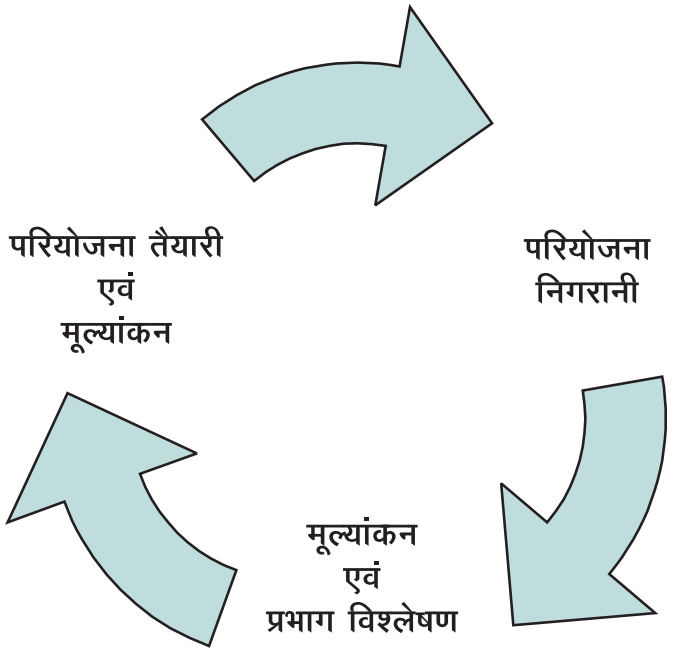

पहले से ही अपनाए गए तौर-तरीके निम्नलिखित हैं :

- तकनीकी, वित्तीय और व्यवहार्यता की दृष्टि से परियोजना प्रस्तावों की कड़ी जांच की जाती है । कई मामलों में संबंधित मंत्रालय के विचार लिए जाते हैं । मूल्यांकन आवश्यकतानुसार एस एफ सी, सी एन ई अथवा मंत्रिमंडल के स्तर पर किया जाता है ।
- परियोजना निगरानी समिति क्रियान्वयन प्रक्रिया का आवधिक मूल्याकंन करती है और इसके कार्य, संभावनाओं के अनुपालन, भौतिक प्रगति और निधियों के समुपयोजन का मूल्यांकन करती है ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में संस्थाओं के साथ गहन क्रियाकलाप किया जाता है ताकि शिक्षण की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो। इसके अलावा भागीदारों से मूल्यांकन भी करवाया जाता है और फीडबैक तत्पश्चात सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है । आईटैक के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए तथा विदेश सेवा संस्थान द्वारा भी यही तौर तरीके लागू किए जाते हैं ।

मूल्यांकन की प्रणाली में और अधिक संशोधन करने के लिए अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- 100 करोड़ के परिव्यय वाली विशाल परियोजनाओं के मामले में किसी व्यावसायिक संगठन के माध्यम से विस्तृत मूल्यांकन कराए जाने का प्रस्ताव है ।
- तकनीकी प्रकार अर्थात पैन अफ्रीका ई-नेटवर्किंग की परियोजनाओं के मामले में सेवा स्तर करारों एस एल ए के मुकाबले क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने का, तकनीकी रूप से सक्षम परियोजना निगरानी एकक और समीक्षा को स्वीकार करने का प्रस्ताव है ।
- पूर्णता के पश्चात स्थानीय प्राधिकारियों और राजदूतावास से मूल्यांकन करवाने का प्रस्ताव है । यह निर्धारित करने के लिए

कि क्या परियोजना का परिणाम प्राप्त किया गया है । जहां संभव होगा वहां लाभग्राही समुदाय से भी फीडबैक लेने का प्रस्ताव है ।

९८ आईटेक के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षुओं/ भागीदारों से फीडबैक प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

नए वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुरूप और हमारे वित्तीय परिव्यय की क्षमता के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से आज परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित नहीं हैं । निजी क्षेत्र की फर्में अब व्यापक क्रिया कलापों में संलग्न हैं जिनमें सिविल निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, निर्मित सामानों की आपूर्ति, प्रशिक्षण इत्यादि शामिल हैं । नेपाल और भूटान में स्थानीय कंपनियों को भी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है और इस प्रक्रिया को अन्य कई क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है । उच्च सम्मान प्राप्त भारतीय निजी फर्में आइटैक नामितों के लिए बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं । गुणवत्ता की संरक्षा करने के साथ-साथ लागत का लाभ उठाने के लिए हम प्रतियोगी बोली प्रणाली का अनुसरण करते हैं ।

वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र

भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान में परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हम सरकारों के निकट संपर्क में रह कर कार्य करते हैं । तदनुसार नेपाल में जिला प्राधिकरण और भूटान में सरकारी विभाग न केवल अनेक सामाजिक और विकासीय परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हैं अपितु कतिपय कार्यों का आंशिक रूप से वित्त पोषण भी करते हैं। भूटान की योजना में परियोजनाबद्ध सहायता, स्थानीय प्राथमिकताओं को पूरा करने वाली क्षेत्रोन्मुख सहायता की दिशा में एक दूसरा प्रयास है जो प्राप्तकर्त्ता की अपेक्षाओं और हमारे समग्र सहायता पैकेज के साथ मेल खाता है । अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में, हम क्रमशः ओ ए यू तथा आसियान के साथ गहन समन्वय करते हैं ताकि उनके प्राथमिक क्षेत्रों को अधिकतम संसाधनों का आबंटन उपलब्ध कराया जा सके । एक अन्य विशेषता, व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, नागरिक सुख-सुविधाओं और अनुभव तथा अन्य सेवाओं तथा संस्था निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की संलग्नता है ।

विकेंद्रीकरण

नेपाल में हमारे साथ त्रिपक्षीय करारों में स्थानीय समुदाय और सरकार गहन रूप से संलग्न है । इससे नेपाली सरकार द्वारा कई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा मिलती है और ऐसे स्थानीय पणधारियों को प्रोत्साहन भी जो इसकी अनवरत सफलता के लिए परियोजना और कार्य में भाग लेते हैं । परियोजना निगरानी का अधिकांश कार्य उस देश में स्थित हमारे आवासी मिशन द्वारा किया जाता है जहां परियोजना का क्रियान्वयन हो रहा है ।

सामाजिक और महिला-पुरुष सशक्तिकरण

वर्तमान में हमारी नीति में महिला पुरुष मसलों पर केंद्रित पृथक

परियोजनाएं अथवा आबंटनों के लिए प्रावधान नहीं है । तथापि स्थानीय समुदायों के अधिक शामिल होने से अब अधिकतर परियोजनाएं महिला-पुरुष संबंधी मसलों से संबंधित होती हैं । अब हमारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, सांस्कृतिक परिरक्षण, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराती हैं । प्रयास है कि भागदारी के माध्यम से सशक्तिकरण उपलब्ध कराया जाए । मंत्रालय में महिला-पुरुष मसलों को अब अपेक्षाकृत अधिक सुविचारित रूप से उठाया जा रहा है और महिला एवं बाल विकास विभाग के परामर्श से महिला-पुरुष बजटीय कक्ष का गठन किया गया है जो सभी ऐसे मसलों पर विचार करने के लिए केंद्र बिंदु है जिनमें इस मंत्रालय में कार्यरत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उपाय भी शामिल हैं ।

पारदर्शिता

न केवल निर्धारित नियमों के अनुपालन और लेखा परीक्षा जांच के लिए प्रस्तुतियों में अपितु स्थनीय समुदायों के प्रति जवाबदेही में भी परदर्शिता बरती जाती है । परियोजनाओं को लांच करने के लिए प्रचार कार्यों को आयोजित किया जाता है, फिल्मों और डी वी डी तैयार करने के जरिए, आवेदकों द्वारा परियोजना निगरानी इस उद्देश्य को पूरा करते हैं । सूचना का अधिकार और इसे उपलब्ध कराने से मंत्रालय जागरुकता और पारदर्शिता का संवर्धन करने में सक्षम होता है । परिणाम बजट भी वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

मंत्रालय ने सामानों और सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के लिए भी प्रयास प्रारंभ किए हैं । विभिन्न मदों के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु निविदाओं का विवरण व्यापक प्रचार एवं पारदर्शिता के लिए मंत्रालय के वेबसाइट में भी डाला जाता है ।

नगद लेन-देन न्यूनतम हो गया है और अब मंत्रालय सभी भुगतान, जिनमें कर्मचारियों का वेतन और अधिप्राप्तियां भी शामिल हैं, चैकों/ड्राफ्टों अथवा इलेक्ट्रोनिक तरीके से किए जाते हैं ।

वर्तमान में, परिणाम बजट का प्रयोग मंत्रालय के भीतर व्यापक रूप से प्रचालन में है । परिव्ययों को परिणामों से संबद्ध करने की अवधारणा के महत्व को समझने और समान्य परियोजनाओं से आगे तथा कार्यक्रम प्रतिमान जिनके प्रति परिणाम बजट अधिक जिम्मेदार होते हैं, के क्षेत्रों में इसे लागू करने का प्रयास रहा है । यह स्वयं में ही एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करता है । कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र, जिनमें परिणामों की मात्रा का मूल्यांकन करने का प्रारंभिक प्रयास किया गया है, उनमें मिशनों और पासपोर्ट कार्यालयों दोनों में कोंसली कार्य के कंप्यूटरीकरण का प्रयास, मंत्रालय के कंप्यूटरीकरण की योजना, अनुदान सहायता के संवितरण की प्रक्रिया को कारगर बनाना; और मंत्रालय द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है ।

वार्षिक बजट, निष्पादन बजट और परिणाम बजट सहित समग्र बजट प्रक्रिया में मंत्रालय को श्रेष्ठ बजट आबंटनों, क्रियान्वयन की सक्षम प्रणालियों के संचालन और व्यय नियंत्रण के लिए तंत्रों के विकास हेतु व्यापक उपकरण उपलब्ध कराए हैं । तथापि गौरतलब है कि यह प्रक्रिया अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी बहुत से सुधारों की गुंजाइश है ।

वार्षिक योजना (2005-06) की समीक्षा

परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्य (2005-2006) और वास्तविक उपलब्धियों का विवरण

क्र0 सं0	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06 (करोड.रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रिया/ समय सीमा	31.03.2006 तक कालम(5)के संदर्भ में परिलब्धियां	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भूटान को सहायता	1020 मेगावाट ताला जल विद्युत परियोजना का निर्माणः भारत मांग/आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए जल विद्युत प्राप्त करेगा।	696.66	ताला जल विद्युत परियोजना से भारत के सम्बद्ध राज्यों को बिजली उपलब्ध होगी	यह परियोजना वर्ष 2007-2008 के दौरान पूरी तरह प्रारंभ होने की उम्मीद है ।	निर्माण कार्यक्रम और वित्तीय परिणाम सन्तोष जनक है	पहली यूनिट के वर्ष 2006-2007 के दौरान प्रारम्भ होने की उम्मीद है ।
		दुगसम सीमेंट योजनाः आर्थिक सम्पर्क सुदृढ़ करेगी, पूर्वोत्तर राज्यों को भी सीमेंट प्राप्त होगा । भूटान के विकास प्रयासों में सहायता	10.00	इस क्षेत्र में आधार भूत विकास/ पूरा होने पर 1 मिलियन टन सीमेन्ट	मुख्य योजना के लिए परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप तैयार हो रहा है ।	आधार संरचना विकास पर 1.18 रूपए का उपयोग हो चुका है	संयुक्त उद्यम भारतीय भागीदारी से स्थापित किया गया। डी आई पी पी के साथ विचार विमर्श करके संरचना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।
		पुनात्सांगछू –I एचई पी(1100 मेगावाट): पुनात्सांगछू –I एचई पी के लिए अतिरिक्त कार्य/जांच	1.996	पी.एच.ई. पी के निष्पादन में सहायता	इसके वर्ष 2007 के अन्त तक समाप्त होने की उम्मीद है	''वापकोस'' द्वारा डी पी आर' तैयार की जा रही है ।	प्रारूप डी पी आर, 2006 में पी एच ई पी को सौंपी गई। अतिरिक्त कार्य के लिए डी पी आर तैयार की जा रही है।
		विकास राज सहायता	175	वितरित राज सहायता	भूटान को वार्षिक बजट राज-सहायता	भूटान को वितरित निधि	यह विकास सहयोग से सबंद्ध करार का भाग है ।
		चुखा राज सहायता भारत में पूर्वी राज्यों में राज सहायता से दी गई विद्युत	74.06	लाभ भोगी राज्यों में विद्युत में मांग आपूर्ति अन्तर को पूरा करने के लिए	भूटान से चुक्खा विद्युत की वार्षिक खरीद	विद्युत की प्रति उपयोगिता के अनुसार दी जा रही राज सहायता	

क्र0 सं0	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06 (करोड.रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रिया/ समय-सीमा	31.03.2006 तक कालम(5)के संदर्भ में परिलब्धियां	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भूटान को सहायता (जारी)	भूटान को राहत मूल्य पर बढ़िया मिट्टी के तेल तथा तरल पेट्रेलियम गैस की आपूर्ति	27.81	भारत-भूटान सीमा के आर पार एस के पी/एल पी जी की तस्करी को रोकना भूटान के साथ हमारी विकास भागीदारी का एक घटक है ।	भूटान को एस के ओ/ एल पी जी की वार्षिक आपूर्ति	आबंटित राशि 15000 एस के ओ का के एल और एल पी जी 6000 एम टी थी	उपयोगिता भूटान द्वारा वास्तविक आहरण पर निर्भर करती है
		सीमा शुल्क लौटाना-भूटान को भारत के निर्यात को संवर्द्धित करने और मुक्त व्यापार प्रणाली के अन्तर्गत राज्स्व की हानी के लिए भूटान को मुआवजा	50.62	यह भूटान के साथ भारत की भागीदारी का एक घटक है ।	सीमा शुल्क की वार्षिक वापिसी	वर्ष 2001 के लिए दावा की गई राशि भूटान की शाही सरकार को लौटा दी गई	राजस्व विभाग वापिस किए गए देय के मूल्यांकन का वार्षिक कार्य करता है ।
		परियोजना बद्ध सहायता भूटान के साथ हमारी विकास भागीदारी के भाग के रूप में भूटान का समाजिक-आर्थिक विकास	137.91	समाजिक- आर्थिक विकास से समयबद्ध परियोजनाओं के द्वारा भूटान के साथ हमारी विकास सहयोग के कार्यान्वयन में सहायता	67 ऐसी परियोजनांए है, जिन्हें भूटान की नौवी पंचवर्षीय योजना (2007-2008)को भारत की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है ।	कुल 67 ऐसी परियोजनांए हैं, जिनमें से 11 परियोजनाओं को मार्च 2006 तक सफलता पूर्वक पूरा किया गया है ।	अधिकतर शेष परियोजनाएं जून, 2008 तक पूरा होने की उम्मीद है ।

टिप्पणी वर्ष 2006 -2007 में विदेश मंत्रालय में परिव्यय बजट आरम्भ किया गया था । इससे पूर्व, भूटान, जो योजना निधियों का अकेला प्राप्तकर्ता, था में केवल योजना परियोजनाओं के लिए निष्पादन मूल्यांकन किया । अतः वर्ष 2005 -2006 के लिए पूर्व निष्पादन का पुनरीक्षण भूटान में परियोजना के लिए था ।

वार्षिक योजना (2006-07) की समीक्षा

परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्य (2006-2007) और वास्तविक उपलब्धियों का विवरण

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य /परिणाम	परिव्यय 2006-2007 (करोड रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रियाएं/ समय-सीमाएं	31.12.2006 तक कालम 5 के सन्दर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रकाशन और प्रचार-प्रसार	. फीचर फिल्मों के अधिकार लेना और खरीद, डाक्यूमेन्टरी फिल्मों की डबिंग/स्क्रीनिंग फोटोग्राफ/प्रदर्शनियां ए.एन.आई. एपीसोड अंशदान, इत्यादि . विभिन्न प्रकाशनों का मुद्रण विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों के पुस्तकालयों तथा विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए पुस्तकों की खरीद और विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों के लिए पत्र-पत्रिकाएं 'इन्डिया पर्सपेक्टिव पत्रिका का प्रकाशन' .भारत और विदेश में प्रैस क्लबों थिंक टेंक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ क्रियाकलाप के माध्यम से भारत की विदेश नीति की प्रस्तुति . प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन, विदेशी पत्रकारों यात्राओं और अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्राओं की व्यवस्था	18.00	. 3 फोटो प्रदर्शनियां आयोजित की . 7 डाक्यूमेन्टरी पूरी की गई . 13 नई डाक्यूमेन्टरी प्रारम्भ की गयी . विदेश महोत्स्वों के लिए 21 फीचर फिल्में ली गई . 7 नए प्रकाशन . इन्डिया पर्सपेक्टिव पत्रिका की प्रति माह 65000 प्रतियां	एक वर्ष	लक्ष्य प्राप्त किया, सिवाय ''इन्डिया पर्सपेक्टिव के जिसे प्रशासनिक कारणों से प्रकाशित नहीं किया गया (प्रकाशन की प्रक्रिया के लिए पुनःनिविदा के कारण)	

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य /परिणाम	परिव्यय 2006-2007 (करोड. रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रियाएं/ समय-सीमाएं	31.12.2006 तक कालम 5 के सन्दर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	पासपोर्ट तथा उत्प्रवासन	. पासपोर्ट कार्यालयों की नेट वर्किंग . हार्डवेयर का अपग्रेडेशन 'पासपोर्ट फाइलों की स्कैनिंग . यात्रा दस्तावेजों का मुद्रण . मशीन द्वारा पढनीय प्रिंटरों की व्यवस्था .विदेश स्थित कुछ चुनिंदा मिशनों में पासपोर्ट वीजा तथा कांसली सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण	154.98	. केन्द्रीय डाटा-बेस का अपग्रेडेशन . लगभग 50 लाख पासपोर्ट आवेदन-पत्र फाइलों की स्कैनिंग . 51 लाख पासपोर्ट पुस्तिकाओं और 35 लाख वीजा स्टीकरों की प्राप्ति . मशीन से पठनीय 100 पिन्टरों की स्थापना . विदेश स्थित ''मिशनों का कम्प्यूटरीकरण बहरीन, बर्मिघंम, न्यूयार्क सान फ्रांसिस्को, मस्कट टोरन्टों, जद्दा, कुआलालम्पुर, दुबई मैड्रिड और पेरिस)''	एक वर्ष	.केन्द्रीय डाटा बेस (पी आई एस ओ एन)का उन्नयन .लगभग 36 लाख पासपोर्टों का स्कैनिंग . 44 लाख पासपोर्ट पुस्तिकाओं और 28 लाख वीजा स्टीकरों की प्राप्ति . मशीन से पठनीय 77 प्रिंटरों की स्थापना .11 मिशनों में कम्प्यूटरीकरण का कार्यान्वयन अन्तिम अवस्था है जो मात्र 2007 में पूरा होने की उम्मीद है ।	शेष काम/खरीद प्रगति पर है

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य /परिणाम	परिव्यय 2006-2007(करोड. रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रियाएं/ समय-सीमा	31.12.2006 तक कालम 5 से सन्दर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां /जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	प्रशिक्षण (विदेश सेवा संस्थान)	. विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन .भा. वि. से. से परिवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना . विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठयक्रमों का आयोजन . विदेश मंत्रालय से इतर अधिकारियों राजनयिक सदृश इत्यादि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	3.77	. विदेशी राजनयिकों के लिए 3 व्यावसायिक पाठ्यक्रम . भा.वि.से. परिवीक्षार्थियों को वर्ष भर का प्रशिक्षण . विदेश मंत्रालय के सहायकों/क्लर्कों (वीपीसी) अनुभाग अधिकारियों, अवर सचिवों के लिए 5-6 पाठ्यक्रम . सेवारत मिशन प्रमुखों/केन्द्र प्रमुखों, राजनयिक सृदश, विदेश मंत्रालय से इतर अधिकारियों इत्यादि के लिए 2-3 पाठयक्रम आयोजित करना	एक वर्ष	.विदेश सेवा संस्थान ने वर्ष 2006-07 में निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं : 'आसियान' राजनयिकों के लिए 1 पीसीएफडी (प्लस 1 पीसी एफ डी) . भा.वि.से. परिवीक्षार्थियों के लिए वर्ष भर का प्रशिक्षणके लिए वर्ष भर का प्रशिक्षण .भा.वि.से (ख) के अवर सचिवों के लिए 1 पाठ्यक्रम अनुभाग अधिकारियों/सहायकों/ क्लर्कों के लिए 4 बी पी सी, अनुभाग अधिकारियो के लिए 1 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम .राजनयिक सदृशों के लिए 1 पाठ्यक्रम .मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारियों के लिए एक पाठ्यक्रम . सुरक्षा गार्डों के लिए एक अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम	योजना के अनुसार काय कलाप किए गए

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य /परिणाम	परिव्यय 2006-2007(करोड. रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रियाएं/ समय-सीमा	31.12.2006 तक कालम 5 से सन्दर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां /जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के लिए सहायता अनुदान	सांस्कृतिक राजनय विदेशों में भारतीय संस्कृति का संवर्द्धन और अन्य देशों को भी अपनी संस्कृति दिखाने के लिए एक मंच दिया	68.50	. विदेशों में 15 प्रदर्शिनियां . विदेशी छात्रों को 1300 छात्रवृत्तियां . 20 विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों और 70 बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों की मेजवानी . बाहर से आने वाले 15 और बाहर जाने वाले 50 विशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं के कार्यक्रम	जारी	'विदेशों में आयोजित 11 प्रदर्शिनियां . विदेशी छात्रों को दी गई 1300 छात्रवृतियां (408 अफगानी छात्र) . 27 विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों की मेजवानी और 94 सांस्कृतिक शिष्टमंण्डल बाहर गए . देश से बाहर जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के 58 यात्रा कार्यक्रम और बाहर से आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के 13 यात्राओं के कार्यक्रम का आयोजन .10 अर्ध प्रतिमाएं/ प्रतिमाएं विदेश भेजी गई .विदेश में 2 भारत महोत्सव बेल्जियम और जापान में आयोजित किए गए	निधियों की कमी के कारण गिरावट शेष यात्रा की तैयारी की जा रही है। इससे पहले योजना नहीं थी

क्र0 सं0	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2006-07 (करोड.रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रिया/ समय-सीमा	31.12.2006 तक कालम(5)के संदर्भ में परिलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (i) बंगलादेश		20.00				
		भारत के प्रति बंगलादेश की जनता के बीच सद्भावना विकसित करना		• खाद्य राहत सहायता प्रदान करना • सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना • कल्याण संबंधी गतिविधियां • संस्थानों/ऐतिहासिक भवनों इत्यादि की मरम्मत/ नवीकरण	1-4 वर्ष में पूरी की जाने वाली अपेक्षित गतिविधियां	• कुल 13000 मी.टन चावल के 2 ट्रेंच भेजे गये हैं • मूल सूचना प्रौद्योगिकी दक्षताओं में 275 शिक्षकों का प्रशिक्षण • 620 कम्प्यूटर और प्रिंटर उपहार में दिए गए ।	• भारत सरकार की सहायता स्थिति के मूल्यांकन के अनुसार भेजी गयी थी • उन कार्यों के ब्यौरे जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

टिप्पणियां :

1. बंगलादेश में सूचना प्रैद्योगिकी साक्षरता फैलाने और नौकरी के अवसरों में वृद्धि में सहायतार्थ मूल सूचना प्रौद्योगिकी में 600 बंगलादेशी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।
2. बंगलादेश के मुक्तियोद्धाआं (स्वतंत्रता सेनानी) के लिए कल्याण गतिविधियों में बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना और इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों में योगदान करना जिसमें भारत के प्रति काफी अच्छी भावनाएं हैं।
3. गाँधी आश्रम ट्रस्ट, लिबरेशन वार म्यूजियम जैसे संस्थानों/ ऐतिहासिक भवनों की मरम्मत/नवीकरण, ढाका यूनिवर्सिटी सीनेट हॉल, बंगलादेश बौद्ध कृषि प्रचार संघ इत्यादि के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है ताकि भारत अपने महत्वपूर्ण् पड़ोसी देश में उदार/सहनशीन राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित कर सके जिसकी सीमा भारत के पूर्व और उत्तर पूर्व में 5 राज्यों से मिलती है ।

क्र0 सं0	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2006-07 (करोड.रूपए में)	मा परक संविवरण	प्रक्रिया/ समय-सीमा	31.12.2006 तक कालम(5)के संदर्भ में परिलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
6	भूटान को सहायता	1020 एम0वी. ताला विद्युत परियोजना भारत मांग/आपूर्ति का अंतर पूरा करने के लिए जल विद्युत प्राप्त करेगा	88.00	ताला जल विद्युत परियोजना से भारत के संगत राज्यों को बिजली उपलब्ध होगी	इस परियोजना के 31 मार्च 2007 तक पूरी तरह से आरंभ होने की संभावना है ।	दिसम्बर, 2006 के अंत में 766 मिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ और पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ने विभिन्न राज्यों में आपूर्ति हेतु 100.13 करोड. रू0 की विद्युत का आयात किया गया ।	
		डुंगसुम सीमेंट संयंत्र द्विपक्षीय आर्थिक संपर्कों को सुदृढ. करना, उत्तर-पूर्वी राज्य सीमेण्ट प्राप्त करेंगे, भूटान के विकास प्रयासों को सहायता प्रदान करना ।	45.00	उस क्षेत्र में आधार भूत सड.क। सम्पन्न होने पर 1 मिलियन टन सीमेन्ट।	सड.क विकास से संबंधित कार्य प्रगति पर है । सीमेण्ट संयंत्र के संपन्न होने के लिए निर्धारित समय-सीमा 27 महीने है ।	सडक तैयार करने का कार्य आरम्भ हो चुका है । संयंत्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मैसर्स होल्टेक द्वारा तैयार की गई है और विचाराधीन है ।	प्रदान की जाने वाली सहायता के स्वरूप को अतिम रूप दिया जा रहा था। भारतीय भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा ।
		पुनातासंगछू –I जल विद्युत परि0 (1100 एम0वी0): पुनातासंगछू –I जल विद्युत परि0 के लिए अतिरिक्त कार्य/जांच हेतु विस्तृत परियोजना रिपोट।	1.29	निर्माणपूर्व गतिविधियों पर कार्य आरम्भ करना। पी.एच.ई. पी के निष्पादन में सहायता।	निर्माण पूर्व गतिविधियों के 2007 के अंत तक पूरा होने का अनुमान है।	पी.एच.ई.पी के लिए प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जून, 2006 में वेपकॉस द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है । अतिरिक्त कार्य के लिए विस्तृत परि0 रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।	निर्माणपूर्व गतिविधियां शीघ्र आरंभ होंगी और वास्तविक निर्माण अगली योजना के तहत होगा।
		विकास सहायता	117.50	सहायता वितरण	भूटान को प्रदान की जाने वाली वार्षिक बजटीय सहायता	भूटान को वितरित निधियां	विकास सहयोग पर यह हमारे करार का एक भाग है।

क्र0 सं0	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2006-2007(करोड.रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रिया/ समय-सीमा	31.12.2006 तक कालम(5)के संदर्भ में परिलब्धियां	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
	भूटान को सहायता (जारी)	चुखा सहायता में भारत पूर्वी राज्यों को सस्ती विद्युत प्रदान करना।	73.92	लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए।	भूटान से विद्युत का वार्षिक क्रय।	विद्युत के उपभोग के अनुरूप सहायता निर्मुक्त की गई ।	सहायता पी.टी.सी.द्वारा विद्युत के वास्तविक आहरण के आधार पर प्रदान की जाती है।
		भूटान को सस्ती दरों पर उच्च कोटि के मिट्टी के तेल और तरल पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति	9.96	भारत भूटान सीमा पर उच्च कोटि के मिट्टी के तेल/एल.पी.जी की तस्करी को रोकना भूटान के साथ हमारी विकास भागीदारी का एक घटक है।	भूटान को उच्च कोटि के मिट्टी के तेल/एल.पी.जी. की वार्षिक आपूर्ति।	10692 कि.ली.उच्च कोटि के मिट्टी के तेल और 3733 मीट्रिक टन तरल पैट्रोलियम गैस की आपूर्ति भूटान को की जा चुकी है।	उपयोग भूटान द्वारा वास्तविक आहरण पर निर्भर करता है।
		उत्पाद शुल्क की वापसी-भूटान में भारतीय निर्यात का संवर्धन करना और मुक्त व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत भूटान को हुई राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए।	38.07	यह भूटान के साथ भारत की विकास भागीदारी का हिस्सा है।	उत्पाद शुल्क की वार्षिक वापसी	वर्ष 2002 के लिए दावा राशि भूटान की शाही सरकार को लौटा दी गई है।	राजस्व विभाग नीयत धन वापसी का वार्षिक मूल्यांकन करता है।
		परियोजना संबद्ध सहायता	164.41	यह सहायता भूटान के समाजार्थिक विकास के लिए है और भूटान के साथ हमारे विकास सहयोग के अनुरूप है।	ऐसी 70 परियोजना है (67 पुरानी 33 नई) जिन्हें भूटान की नौंवी पंचवर्षीय योजना (2002-2008) के प्रति भारत के सहयोग के तौर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।	अधिकांश परियोजनाओं को संतोषजनक स्तरों पर क्रियान्वित किया जा रहा है और वे लगभग पूरी होने वाली है। अधिकांश परियोजनाओं के जून 2008 तक पूरा होने की संभावना है।	सितंबर 2006 में हुई समीक्षा के उपरांत उन परियोजनाओं को बंद कर दिया गया/अगली योजना के तहत डाल दिया गया, जो आरंभ नहीं हुई थीं अथवा धीमी गति से बढ. रही थीं।

क्र0 सं0	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2006-2007(करोड.रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रिया/ समय-सीमा	31.12.2006 तक कालम(5)के संदर्भ में परिलब्धियां	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
7	नेपाल को सहायता	एन.एच.पी.सी. को भुगतान- महाकाली संधि के अंतर्गत व्यक्त प्रतिबद्धता की पूर्ति	5	टनकपुर जल विद्युत परियोजना से नेपाल को विद्युत की आपूर्ति। महाकाली संधि के अंतर्गत व्यक्त प्रतिबद्धता।	नियमित वार्षिक भुगतान	3.8 करोड. रू. की पहली किस्त प्रदान की जा चुकी है जबकि 4.7 करोड. रू0 की दूसरी किस्त प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में है।	वृद्धि का कारण ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसरण में एन.एच.पी.सी.द्वारा प्रभारों में वृद्धि करना है।
		लघु विकास परियोजना स्कीम-नेपाल के समाजार्थिक विकास में सहायता प्रदान करना। शिक्षा, स्वास्थ्य और समुदाय विकास के क्षेत्र में।	36	इस स्कीम के अंतर्गत 3 करोड. नेपाली रूपयों से कम की लघु परियोजनाओं पर विचार किया जाता है और इनकी निगरानी मिशन द्वारा की जाती है। :स्वास्थ्य : 17 परियोजनाएं : शिक्षा : 73 परियोजनाएं : समुदाय विकास : 10 परियोनाएं	इन परियोजनाओं की अवधि 18-24 महीने है।	अब तक 20.53 करोड. रू0 की राशि का व्यय हो चुका है।	दिसंबर 2006-फरवरी 2007 के बीच तराई क्षेत्र में हुए उपद्रव के कारणवश लघुविकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हो सकता है।
		नेपाली छात्रों को छात्रवृत्ति-नेपाल के मानव संसाधन विकास में सहायता।	6.00	भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए तथा नेपाल में छात्रवृत्तियां प्रदान करना।	नियमित वार्षिक भुगतान	1.5 करोड. रू0 की राशि प्रदान की है। भारत में 282 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं और नेपाल में इसकी संख्या 550 से दोहरी होकर 1100 हो गई है।	

क्र0 सं0	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिव्यय	परिव्यय 2006-2007(करोड रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रिया/ समय-सीमा	31.12.2006 तक कालम(5)के संदर्भ मं परिलब्धयां	टिप्पणियां/जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
	नेपाल को सहायता (जारी)	बीर अस्पताल का विस्तार-काठमांडू में इमरजैंसी अस्पताल और ट्रौमा सेंटर की स्थापना।	25.00 (कुल लागत : 63.31 करोड.)	200 बिस्तर के अस्पताल की स्थापना हतु सितंबर 2006 में ठेका प्रदान किया गया	सिविल निर्माण अवधि 18 महीने है।	2.5 करोड. की राशि का व्यय किया जा चुका है।	ठेका प्रदान करने में विलंब और तराई में हए उपद्रव ने परियोजना के क्रियान्वयन और निधि के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
		मनमोहन अधिकारी पॉलिटैक्निक -तराई क्षेत्र के उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल कामगार प्रदान करने हेतु।	12.00 (*कुल लागत*: 19.54 *करोड.*)	पॉलिटैक्निक की स्थापना भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। स्थल क्षेत्रफल : 4 हेक्टेयर, कुल आवृत्त क्षेत्रफल : 13079.28 व.मी.। तीन क्षेत्र : इलैक्ट्रानिक्स, इलैक्ट्रिकल्स और मैकेनकल। भारत से आरंभिक संकाय सहयोग। भूमि एम.एम.ए. ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त।	सिविल निर्माण फरवरी 2007 तक पूरा किया जाना है।	विराट नगर क्षेत्र (मोरांग जिला) में प्रशिक्षित कामगार प्रदान करना। यह संस्थान नेपाल में अपने किस्म का पहला संस्थान होगा।	दिसंबर 2006 - फरवरी 2007 के दौरान तराई में कानून और व्यवस्था की स्थिति और उपद्रवों से परियोजना के 2-3 महीने देर से पूरा होने की संभावना है।
		नेपाल को बजट अनुदान-नेपाल सरकार को परोक्ष बजट अनुदान सहायता जारी रखी गयी है।	100.00	सहायता के माध्यम से बजट अनुदान। इससे भारत के लिए पर्याप्त सद्भावना उत्पन्न हुई।	तत्काल।	अगस्त 2006 में प्रदत्त ।	जून 2006 में भारत में प्रधानमंत्री कोइराला की यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसरण में।
		15000 मीट्रिक टन यूरिया और 10000 मीट्रिक टन डी.ए.पी.की आपूर्ति-नेपाल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता।	18	25000 मीट्रिक टन उर्वरक प्रदान करन के लिए सहायता हेतु भुगतान। इससे भारत के लिए सद्भावना उत्पन्न हुई।	तत्काल।	सितंबर 2006 में आपूर्ति कर दी गई और सहायता घटक के तौर पर उर्वरक विभाग को 15.75 करोड. रू0 का भुगतान किया गया।	जून 2006 में भारत में प्रधानमंत्री कोइराला की यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसरण में।

क्र0 सं0	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिव्यय	परिव्यय 2006-2007(करोड रूपए में)	मात्रा परक संविवरण	प्रक्रिया/ समय-सीमा	31.12.2006 तक कालम(5)के संदर्भ मं परिलब्धयां	टिप्पणियां/जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
8	अन्य देशों, श्रीलंका के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग।		28.02				
		भारत के लिए आम सद्भावना हासिल करना और भारत के दीर्घावधिक हितों को विकसित करना।		900 श्रीलंका रक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण –सूनामी राहत परियोजनाएं। -श्रीलंका के मध्य प्रांत में 150 बिस्तर के अस्पताल का निमाण। - कैंसर अस्पताल के लिए अनुदान	1 वर्ष	श्रीलंका के 914 रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। - दक्षिणी रेलवे गलियारे का व्यवहार्यता अध्ययन निष्पादित। - सेनानायक समुद्रम रिजर्वायर की दरार का मरम्मत कार्य निष्पादित। - त्रिंकोमाली परियोजना के ब्यौरो को अंतिम रूप दिया जा रहा है। - शल्य कक्ष का नवीकरण और ओ बी जी वाई उपस्कर की आपूर्ति संपन्न। - प्रक्रियाधीन	इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन श्रीलंका में अनुकूल परिस्थितियों की बनी रहने और श्रीलंका के प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त सहयोग पर आधारित है।

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07(करोड़ रू. मे)	मात्रा संविवरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग मालदीव	भारत के लिए सामान्य सद्भावना और भारत के दीर्घावधिक हितों को बढ़ावा देना।	6.00	- मालदीव के रक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण - उपकरणों की आपूर्ति सहित जल विज्ञान सर्वेक्षण एकक की स्थापना - आतिथ्य सरकार और पर्यटन अध्ययनों के संकाय की स्थापना	एक वर्ष	- मालदीव के 100 रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण -अगले वर्ष के दौरान परियोजना आरंभ करने और पूरा करने का निर्णय - सी एन ई का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। सिविल निर्माण और उपकरणों की आपूर्ति शीघ्र आरंभ होगी।	

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07(करोड़ रू. मे)		मात्रा संविवरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
10.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहायता म्यांमा		(योजना) 4.57	(गैर-योजना) 40.00				
		म्यामां में अवसंरचना विकास, संवर्धित सड़क संपर्क, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में म्यामां के साथ सहयोग को बढ़ावा, सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग, भारत के लिए सद्भावना निर्माण			-कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना -तामू-कलेमयो कलेवा सड़क का निर्माण/अनुरक्षण -दूर-संवेदन में सहयोग -सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं -सड़कों को जोड़ना -तामान्थी पनबिजली परियोजना - तमान्थी पनबिजली परियोजना		-डी पी आर को अंतिम रूप दिया गया है और इसकी जांच की गयी है। -म्यामां के साथ प्रोतोकोल संपन्न किये गये हैं । -बी आर ओ ने उपकरण प्राप्त कर लिये हैं, मानसून के बाद निर्माण आरंभ होगा । - ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन के उन्नयन के लिए पहली किश्त उपलब्ध करायी गयी है। - परियोजना के ब्यौरों पर म्यामां के साथ चर्चा की जानी है।	- मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। तौर-तरीकों के संबंध में म्यामां के साथ आगे चर्चा की जाएगी । - डी पी आर तैयार किया जा रहा है । - परियोजनाएं विचाराधीन हैं - डी पी आर पर म्यामां की टिप्पणी प्रतीक्षित है ।

क्र. सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07 (करोड़ रू. मे)	मात्रा संविवरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	अफगानिस्तान को सहायता	पुल-ए-खुमरी से काबुल तक पारेषण लाइन- इस परियोजना से काबुल को उजबेकिस्तान से विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। इससे अफगानिस्तान के उद्योग और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।	107.44	बुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220 के वी डबल मर्किट पारेषण लाइन का निर्माण । काबुल में 220/110/20 के वी उप-स्टेशन का निर्माण	ठेका अगस्त 2005 में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया और इसके फरवरी, 2009 में पूरा होने की आशा है।	- उप स्टेशन के स्थल को बारूदी सुरंगों से रहित किया गया है । एक स्थानीय सिविल ठेकेदार के जरिए भेल ने चहारदीवारी निर्माण कार्य आरंभ किया है । मुख्य उपकरणों के संबंध में इंजीनियरिंग और खरीद निर्माण कार्य आरंभ हुआ है । तीन बी पी आई के पी ओ स्थापित किये गये हैं । खरीदे जाने वाले सामानों का क्रय पत्र जारी किया गया है और उपकरणों को समय से प्राप्त किया जाएगा। - 220 के वी के पुल-ए-खुमरी पारेषण लाइन (के.ई. सी.लि. द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है) का निर्माण 21 अक्तूबर, 2005 को ठेका दिया गया । 202 किमी को वारूदी सुरंगों से मुक्त किया गया है; 202 किमी में से 137 का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है (अनुमान से 23 किमी अधिक) प्रस्तावित 615 में से 317 स्थानों में आधारशिला रखी जा चुकी है (अनुमान से 135 अधिक)। 615 में से 142 अवस्थितियों पर टावर बनाये जा चुके हैं (अनुमानित 60 की तुलना में)। इंसुलेटरों की पहली खेप का निरीक्षण किया जा चुका है और नवम्बर, 2006 में माप कार्य आरंभ हुआ ।	पारेषण लाइन कार्य का 23 प्रतिशत पूरा हो चुका है । कार्य कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है और कतिपय क्षेत्रों में निर्धारित अवधि से पूर्व भी।
		राहत और पुनर्वास		-स्कूली बच्चों के लिए बिस्कुट का प्रावधान - कौशल में सुधार		- विश्व खाद्य कार्यक्रम के जरिए संवर्धित गेहूँ की आपूर्ति की जा रही है। - कारीगरी कौशल में समुदायों को प्रशिक्षित करने के लिए सी आई आई के साथ और सामुदायिक विकास के लिए एस ई डब्ल्यू ए के साथ परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है ।	

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07(करोड़ रू. मे)	मात्रा संविवरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहायता अफ्रीकी देशों को सहायता	पश्चिमी अफ्रीकी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के लोगों के बीच भारत के प्रति सद्भाव का सृजन करना	20.00	पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकाः -मेडागास्कर में इंटरनेट नेटवर्क की स्थापना - तंजानियां और सेशल्स में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना - कोमोरोस में कंवेंशन सेंटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण - मोजाम्बिक में काजू प्रसंस्करण इकाई के निर्माण में सहायता		- व्यवहार्यता अध्ययपूर्ण -- व्यवहार्यता अध्ययपूर्ण -- व्यवहार्यता अध्ययपूर्ण - उपस्कर भेज दिया गया है और स्थापना शीघ्र की जाने वाली है ।	

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07(करोड़ रू. मे)	मात्रा संविवरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहायता अफ्रीकी देशों को सहायता	पश्चिमी अफ्रीकी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के लोगों के बीच भारत के प्रति सद्भाव का सृजन करना	20.00	पश्चिमी अफ्रीका - पैन अफ्रीकी टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन परियोजना - पैन अफ्रीकी टेली मेडिसिन और - बेनिन को ट्रैक्टरों की आपूर्ति - बेनिन, नाइजर और कोंगो के लिए कृषि विशेषज्ञ - गिनी को ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति -टोगो को ट्रैक्टरों की आपूर्ति - कोगो को ट्रैक्टरों की आपूर्ति	1 वर्ष 3वर्ष 1वर्ष 1वर्ष	- परियोजना लगाई गयी है और इसका परीक्षण किया जा रहा है । - हब के लिए अवसंरचना बनाई जा रही है । - डिलीवरी को अंतिम रूप दिया जा रहा है । - कोगों और नाइजर में विशेषज्ञ - ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति की जा रही है। - ट्रेक्टरों की आपूर्ति की गयी । - ट्रेक्टरों की आपूर्ति की गयी ।	यह वृहत पैन अफ्रीका परियोजना में एक महत्वपूर्ण योगदान है। - मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ इस पर कार्रवाई की जा रही है। - व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07(करोड़ रू. मे)	मात्रा संविवरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग मध्य एशिया को सहायता	सूचना प्रौधोगिकी क्षेत्र में कौशल विकास क्षेत्र का सामान्य विकास और मध्य एशिया के लोगो के बीच इस क्षेत्र का सामान्य विकास	17.00	सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना - मध्य एशिया के देशों को कृषि उपकरण / औजार उपलब्ध कराना		- विश्केक, ताशकंद, दुशान्बे और अस्ताना में आई टी केन्द्रों की स्थापना के लिए दी गई सहायता - आर्मेनियाँ को 240 ट्रेक्टरों का अनुदान - ताजिकिस्तान को 10 टाटा बसों का अनुदान	

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07 (करोड़ रू. मे)	मात्रा संवितरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
14.	लोक निर्माण	आबुजा, नाइजीरिया में चांसरी का निर्माण	5.00	चांसरी भवन	निर्माण पूर्व कार्यकलाप प्रगति में है । निर्माण कार्य अप्रैल, 07 में शुरू होने तथा जून 2008 में समाप्त होने की आशा है ।	स्थानीय निकाय का अनुमोदन सिद्धांततः प्राप्त कर लिया गया है। ठेकेदारों के पूर्व-अर्हता के लिए प्रैस-विज्ञाप्ति जारी कर दी गई हैं । टेंडर के कागजात को अंतिम रूप दे दिया गया है ।	बोलियां अनुमोदित परियोजना लागत से अधिक हो सकती है।
		बिजिंग, चीन में चांसरी तथा आवासों का निर्माण	8.00	चांसरी एवं आवासों का निर्माण	निर्माण मार्च, 07 में शुरू होने तथा दिसंबर, 2008 में पूर्ण हो जाने की आशा है ।	90.00 लाख रू0 के व्यय की संस्वीकृति जारी कर दी गई है।	
		आलको मुख्यालय का निर्माण	1.00	आलको मुख्यालय के लिए भवन	मई, 2007 के अंत तक परियोजना पूर्ण हो जाने की आशा है।	72.52 लाख रू. की संस्वीकृति जारी कर दी गई है।	
		ब्रासिलिया, ब्राजिल में चांसरी, दूतावास तथा अधिकारियों के आवास	1.00	चांसरी के लिए भवन, दूतावास आवास तथा अधिकारियों के आवास	निर्माण कार्य मई, 2007 में शुरू होने तथा अप्रैल,2009 तक पूरा हो जाने की आशा है।	हुई प्रगति के अधार पर 1.00 करोड़ रू. के आबंटन की समीक्षा की जानी है।	

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07(करोड़ रू. मे)	मात्रा संवितरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	लोक निर्माण (जारी)	एफ एस आई भवन, नई दिल्ली का निर्माण	6.00	एफ एस आई का भवन		संपूर्ण राशि की संस्वीकृति जारी कर दी गई है। एफ एस आई ने इंस्टीट्यूट ब्लॉक से कार्य करना शुरू कर दिया है।	
		ताशकंद, उजबेकिस्तान में चांसरी, दूतावास आवास तथा स्टाफ आवास का निर्माण	1.50	चांसरी, दूतावास आवास तथा स्टाफ आवास के लिए भवन	निर्माण कार्य मई, 2007 में शुरू होने तथा अक्तूबर, 2008 में पूर्ण होने की आशा है।	22.4 लाख रू0 के व्यय की संस्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रौजेक्ट का प्रशासनिक अनुमोदन 1 जुलाई, 2006 को प्राप्त हुआ ।	
		काबुल, अफगानिस्तान में चांसरी तथा आवासों का निर्माण	14.00	चांसरी तथा आवासों के लिए भवन	मध्य अक्तूबर, 2006 को ठेका कार्य सौंप दिए जाने की आशा थी। ठेका नहीं दिया जा सका।	ठेकेदारों से प्राप्त बोली की राशि अनुमानों के लगभग दुगनी थी ।	बोली अधिक होने के कारण परियोजना में विलंब होने की संभावना है ।
		काठमांडू, नेपाल में चांसरी तथा आवासों का निर्माण	8.83	चांसरी तथा आवासों के लिए भवन	निर्माण कार्य मई, 2007 में शुरू होने तथा मार्च 2011 तक पूरा होने की आशा है।	वर्तमान वर्ष में 70.00 लाख रू. की राशि खर्च हुई है । आवंटित राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च होने की आशा नहीं है।	बोली अत्याधिक थी। संशोधित लागत के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है ।

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07 (करोड़ रू. मे)	मात्रा संवितरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/ जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	लोक निर्माण(जारी)	मस्कट, ओमान में चांसरी तथा दूतावास आवास का निर्माण	7.00	चांसरी तथा दूतावास आवास के लिए भवन	निर्माण कार्य जुलाई, 2007 तक पूरा हो जाने की आशा है।	निर्माण कार्य प्रगति में है। 3.47 करोड़ रू. खर्च हो चुके है । आवंटित शेष राशि का भी पूर्णतः उपयोग हो जाने की आशा है ।	
		कुवैत में चांसरी परियोजना के लिए परामर्शदाता के साथ विवाद	0.01	विवाद का निपटान		आवंटित राशि का पूर्णतः उपयोग हो गया ।	
		वारसा, पौलेंड में चांसरी तथा आवासों का निर्माण	5.00	चांसरी तथा आवासों का निर्माण	निर्माण कार्य, 2007 में शुरू होने तथा सितंबर, 2008 में पूर्ण हो जाने की आशा है ।	1.09 करोड़ रू. के व्यय की संस्वीकृति जारी हो गई है। संकल्पना के लिए स्थानीय निकाय का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। पूर्व-अर्हता के लिए प्रैस-विज्ञाप्ति जारी हो गई है । टेंडर कागजात को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	
		कोलकाता में आई सी सी आर क्षेत्रीय कार्यालय परिसर।	1.00	आई सी सी आर के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भवन	निर्माण कार्य अप्रैल,2007 तक पूरा हो जाने की आशा है ।	61.28 लाख रू. का व्यय हुआ है। निर्माण-कार्य प्रगति में है।	

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07 (करोड़ रू. मे)	मात्रा संवितरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	लोक निर्माण(जारी)	लुओयांग, चीन में भारतीय शैली के बौद्ध धर्मस्थल का निर्माण	7.00	भारतीय शैली की बौद्ध धर्मस्थल का भवन	निर्माण कार्य प्रगति में है और जुलाई, 2007 तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।	3.06 करोड़ रू. का व्यय पहले ही हो चुका है । शेष आवंटित राशि का भी पूर्ण उपयोग हो जाने की आशा है ।	
		नैरोबी में चांसरी भवन	.55	चांसरी के लिए भूमि		मूल्यांकन रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं पाया गया ।	
		ब्यूनस आयर्स में चांसरी भवन	11.31	चांसरी के लिए भवन		चांसरी भवन का क्रय किया गया है ।	
		मापुतो में चांसरी भवन	0.27	चांसरी के लिए अतिरिक्त भूमि		अतिरिक्त भूमि की खरीद की गई ।	
		विदेश मंत्रालय के मुख्यालय का निर्माण। जवाहर लाल नेहरू भवन(पूर्व विदेश भवन)	15.00	विदेश मंत्रालय के मुख्याल के लिए भवन	नवंबर, 2008 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की आशा है । तत्पश्चात आंतरिक सज्जा तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा होने में छह माह लगेंगे।	14.11.2006 को निर्माण-कार्य शुरू हो गया है। 5.59 करोड़ रू. की संस्वीकृति जारी हो गई है। शेष आवंटित राशि का भी पूर्ण उपयोग हो जाने की आशा है ।	

क्र.सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07 (करोड़ रू. मे)	मात्रा संवितरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	लोक निर्माण(जारी)	नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय का मुख्यालय तथा कोलंबो, मेक्सिको, करांची, उलान बातर एवं अन्य मिशनों/ केन्द्रों में सरकारी स्वामित्व वाली आवासीय भवनों का आर एंड एम/जीर्णोद्धार	36.53		पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत विदेश स्थित हमारे मिशन में सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों का आर एंड एम कार्य शुरू किया जाना है। मिशनों से अनुरोध प्राप्त होते ही प्रौजेक्ट प्रभाग उन पर कार्रवाई करेगा।	4.09 करोड़ रू. का व्यय हुआ है। शेष बची राशि का उपयोग मिशनों तथा पासपोर्ट कार्यालयों के लिए संपत्तियों की खरीद करने के लिए किया जाएगा।	

क्र. सं.	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2006-07(करोड़ रू. मे)	मात्रा संवितरण/वास्तविक निष्पादन	चरण/समय सीमा	31.12.2006 तक की स्थिति के अनुसार कॉलम(5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम के कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15	आवासीय	इस्लामाबाद में आवासों का निर्माण	1.00	दूतावास आवास के लिए भवन अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए आवास	निर्माण कार्य जुलाई, 2007 में शुरू होने तथा जनवरी,2010 में पूर्ण होने की आशा है।	84.51 लाख रू. का व्यय हुआ है । वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है।	
		8,साउथ ऑडले स्ट्रीट लंदन में 6 आवासों का निर्माण	5.00	आवास के लिए भवन	निर्माण कार्य मई, 2007 में शुरू होने तथा दिसंबर, 2008 में पूर्ण होने की आशा है।	18 लाख रू. का व्यय हुआ है। 88 लाख रू. और व्यय होने की आशा है ।	
		बैंकाक में राजदूतावास आवास तथा सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	1.00	दूतावास आवास तथा सांस्कृतिक केन्द्र के लिए भवन	निर्माण कार्य अप्रैल,2008 में शुरू होने तथा अक्तूबर, 2009 में पूर्ण होने की आशा है ।	कंसल्टेंसी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए है। शीघ्र प्राथमिक प्राक्कलन प्राप्त होने की आशा है ।	
		कीव में आवासों को हटा कर पुनः निर्माण करना	0.03	आवासों के लिए नए भवन	निर्माण कार्य अक्तूबर,2008 में शुरू होने तथा सितंबर, 2010 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।	2.58 लाख रू. का व्यय हो चुका है।	
		करांची, ओस्लो, हेग, रोम, टोकियो, बुडापेस्ट सिंगापुर तथा अन्य मिशनों/केन्दों में सरकारी स्वामित्व की आवासीय भवनों का आर एंड एम/ जीर्णोद्धार	0.97		पूंजीगत परिव्यय बजट के तहत विदेश स्थित हमारे मिशनों में सरकारी स्वामित्व की संपत्तियों का आर एंड एम कार्य किया जाना है। इस आशय के अनुरोध मिशनों से प्राप्त होने पर प्रौजेक्ट प्रभाग उन पर कार्रवाई करेगा।	7.28 करोड़ रू. का व्यय हो चुका है ।	
		जार्ज टाउन में ई आर की खरीद	3.10	दूतावास आवास के लिए भवन		प्रस्तावों को छोड़ दिया गया ।	
		काराकास में ई आर की खरीद	9.90	दूतावास आवास के लिए भवन		ई आर की खरीद की गई।	

अध्याय V – वित्तीय समीक्षा

विदेश मंत्रालय का बजट अधिकांशतः गैर योजना प्रकार का है और गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत आबंटनों में थोड़ी वृद्धि देखने में आई है जबकि पड़ोसी देशों में बड़ी परियोजनाओं के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में योजनागत शीर्ष के अंतर्गत घटते-बढ़ते रहे हैं ।

	ब.अ.2006-07		सं.अ. 2006 07		ब.अ.2007 08	
	गैर योजना	योजनागत	गैर योजना	योजनागत	गैर योजना	योजनागत
राजस्व	3312.74	151.90	3712.74	187.10	3278.98	395.40
पूंजीगत	160.01	70.40	160.01	35.20	654.62	104.60
कुल	3472.75	222.30	3872.75	222.30	3933.60	500.00
सकल योग	3695.05		4095.05		4433.60	

बजट आबंटन में मुख्य रुझान और पुर्वानुमान निम्नलिखित हैः

- वैश्विक कार्यों में भारत की बढती हुई भूमिका को पूरा करने में मंत्रालय के लिए संवर्धित बजटीय आबंटन की आवश्यकता अधिकांश रूप में पूरी हो गई है । तथापि आने वाले वर्षों में उच्चतर स्तर पर बजट में वद्धि करनी होगी ।
- विदेशों में बड़ी परियोजनाओं में संवर्धित भागीदारी की दृष्टि से बजट का बड़ा भाग योजनागत निधियों से पूरा करना होगा । इसके अतिरिक्त अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बढ़ते हुए बजट के कारण योजना गत शीर्ष से पूरा करना होगा ।
- विदेशों में सरकार की वचनबद्धता के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत गैरयोजना खंड में लोक निर्माण और गृह निर्माण के लिए तथा योजनागत खंड में ऋणों और अग्रिमों के लिए भी संवर्धन की आवश्यकता है ।
- संशोधित अनुमान के स्तर पर बजट अनुमान आबंटनों को विशिष्ट रूप से बढ़ाना होगा और संवर्धन की मात्रा बढ़त की ओर ही रही है । मंत्रालय की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जबकि संवर्धन अनिवार्य है तो बजट अनुमान के स्तर पर उच्चतर आबंटन के लिए प्रयास करने होंगे ताकि समुचित आयोजना की जा सके।
- संस्थाओं को अनुदान सहायता का आबंटन संवर्धित आंतरिक राजस्व उत्पादन के लिए आवश्यक है ।

कई वर्षों से व्यय में अधिकता की रुझान देखी गई है और 2006-07 में राजस्व और पूंजीगत दोनों ही खंडों में वृद्धि तथा उपयोग का उच्च स्तर देखा गया है । 2006-07 में पूंजीगत परिव्यय में अधिक प्रावधान किया गया है और उम्मीद है इसका वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग किया जाएगा ।

	2004-05		2005-06		2006-07	
	बजट	% उपभुक्त	बजट	% उपभुक्त	बजट (ब.अ.)	% उपभुक्त (दिस.2006)
राजस्व	3517.36	96.49	3874.58	96.39	3464.64	74.34
पूंजीगत	376.63	96.22	395.42	89.73	230.41	35.70
कुल	3893.99	96.46	4270.00	95.78	3695.05	71.94

मंत्रालय का व्यय बजट आबंटन और वित्तीय नियमों के अनुरूप ही हुआ है । 2006-07 के व्यय पैटर्न ने भी अंतिम समय में व्यय की अधिकता न करते हुए गति पकड़ी है ।

इसके अलावा मुख्य अनुदानों में उपयोग उच्च स्तर पर ही रखा गया है ताकि अभ्यर्पण की संभावना कम से कम हो । मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि बकाया उपयोग प्रमाणपत्र की कोई व्यवस्था नहीं है । बंगला देश को दिए गए ऋण में किंचित चूक के अलावा विदेशी सरकारों से ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सामान्य तौर पर नियमानुसार हैं ।

मंत्रालय की अनुदान सहायता वाली तीन संस्थाएं हैं - भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय विश्व कार्य परिषद और अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली सोसायटी । सभी अनुदानों की व्यवस्था नियमानुसार की गई है ।

मंत्रालय की प्राप्तियों, जो विशेष रूप से पासपोर्ट और वीजा द्वारा प्राप्त हो रही हैं, में भी देश और विदेश दोनों में वृद्धि का रुझान दिखाई पड़ा है ।

	2004-05		2005-06		2006-07 (अनुमानित)	
	पासपोर्ट	वीजा	पासपोर्ट	वीजा	पासपोर्ट	वीजा
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (भारत)	391.00	10.95	455.71	10.70	650.00	750.00
मिशन (विदेश)	138.25	657.72	148.97	703.77		
कुल	529.25	668.67	604.68	714.47	650.00	750.00
% परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)		14.25	6.84	7.50	4.97	

मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन वित्तीय नियमों को लागू करने पर आधारित है । साथ ही साथ मंत्रालय ने अपने कार्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए नया तंत्र शुरू करने के लिए लेखा परीक्षा के परिणामों का उपयोग किया है ताकि प्रणाली को संशोधित किया जा सके और कारगर बनाया जा सके, क्षमताओं को साकार करने के लिए नए तंत्रों और पद्धतियों को अपनाया है । अतिरिक्त रोकड़ शेष रखने को रोकनेके लिए निधियों की प्रेषण प्रणाली इस प्रकार परिवर्तित कर दी गई है कि रोकड़ शेष की समीक्षा हर महीने की जाती है । जबकि विगत में यह समीक्षा हर तिमाही में की जाती थी । अतिरिक्त व्यय/बचत से बचने के लिए व्यय अनुवीक्षण समिति प्रणाली शुरू की गई है ताकि कार्यक्रमों और बजटीय स्थितियों की तिमाही समीक्षा की जाए ।

वित्तीय प्रबंधन में मंत्रालय ने कई सुधारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- व्यय प्रबोधन समिति में त्रैमासिक समीक्षा के माध्यम से खर्च का प्रभावी प्रबंधन । इससे व्यय और परियोजनाओं की निरंतर समीक्षा व्यय की समान गति और फालतू खर्च की रोकथाम होती है ।
- मंत्रालय द्वारा संचालित परियोजनाओं की एक नियमित निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली है । इससे अनुमोदित अनुमानों के भीतर समय पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन और उनसे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति सुकर हो जाती है ।
- मिशनों/केंद्रों के पास उपलब्ध बकाया ओर आगामी माह के लिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रेषणों की मासिक समीक्षा के माध्यम से नकद बकाया पर नियंत्रण ।
- मानकीकरण को सुनिश्चत करने के लिए मिशनों में कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली शुरू की जा रही है । ऑन लाइन बजट प्रणाली शुरू करने की मंत्रालय की योजना है, जिससे क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी ।
- अब अधिकांश भुगतान ई सी एस के जरिए किए जा रहे हैं ।

- इस बात पर बल दिया जाता है कि लेखा परीक्षा पैराओं का निपटान कार्यकरण को कारगर बनाने तथा प्रणालियों में सुधार लाने की दृष्टि से किया जाए । जिन अधिकारियों ने अपनी पात्रता से अधिक राशि का आहरण किया है उनसे होने वाली वसूलियां प्रभावित होती रही हैं ।

- लेखा परीक्षा पैराओं का निपटान कार्यकरण को कारगर बनाने तथा प्रणालियों में सुधार लाने की दृष्टि से किए जाएं । इस बात पर जिन अधिकारियों ने अपनी पात्रता से अधिक राशि का आहरण किया हे उनसे हाने वाली वसूलियां प्रभावित होती रही हैं ।

- पारदर्शिता को बढ़ाया देने के लिए मंत्रालय के लेखे वेबसाइट पर डाले गए हैं ।